

मोपाल

10 जून 2026 बुधवार

आज का मौसम

40.0 अधिकतम
28.0 न्यूनतम

दोपहर मेट्रो



Page-1

बेबाक खबर हर दोपहर

अब मेरे खाते में आते हैं
₹6000

मायग्रेशन जनसंख्या डेटा जारी D11031/26



₹4.3 लाख करोड़ की पीएम किसान सम्मान निधि,
₹26+ लाख करोड़ की MSP पर खरीद,
₹2 लाख करोड़ का फसल बीमा,
8 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जैसे कदमों से देश के अन्नदाता को ताकत

12 विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के



मोदी सरकार के 12 वर्ष... राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और वैश्विक भारत की नई कहानी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बारह वर्ष पूरे कर लिए हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अवधि इतनी लंबी मानी जाती है कि उसके आधार पर किसी भी सरकार की दिशा, दृष्टि और उपलब्धियों का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जा सके। मोदी सरकार के इन बारह वर्षों का अफकलन केवल चुनावी सफलताओं, राजनीतिक लोकप्रियता या विरोधियों की आलोचनाओं के आधार पर नहीं किया जा सकता। असली प्रश्न यह है कि इस दौरान भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक क्षमता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, तकनीकी शक्ति और वैश्विक प्रतिष्ठा में कितना बदलाव आया।



करीब है। आत्मनिर्भरता की यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन मजिल अभी शेष है। मोदी सरकार की सोच का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ विज्ञान और प्रौद्योगिकी रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को अभूतपूर्व राजनीतिक समर्थन और संसाधन प्राप्त हुए। चंद्रयान मिशन की सफलता ने भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया, जो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की क्षमता रखते हैं। यह केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि भारत की तकनीकी प्रतिष्ठा का भी प्रतीक थी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के प्रयासों ने भी हथियार निर्माण में नई संभावनाएं पैदा की हैं। रक्षा क्षेत्र में निजी उद्योगों का प्रवेश लंबे समय तक चर्चा का विषय रहा, लेकिन पिछले दशक में इस दिशा में ठोस प्रगति दिखाई दी है। तकनीक के क्षेत्र में भी भारत ने पहचान बनाई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सुपर कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर निर्माण और डिजिटल भुगतान को लेकर महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए गए हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने दुनिया को डिजिटल भुगतान का भारतीय मॉडल दिखाया है। आज करोड़ों भारतीय प्रतिदिन जिस सहजता से डिजिटल लेन-देन कर रहे हैं, वह एक दशक पहले कल्पना से परे था। आने वाले वर्षों में यही तकनीकी आधार भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में नई भूमिका दे सकता है। विदेश नीति के मोर्चे पर भी भारत की स्थिति पहले की तुलना में अधिक आत्मविश्वासपूर्ण दिखाई देती है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और खाड़ी देशों के साथ संबंधों को संतुलित रखते हुए भारत ने अपने रणनीतिक हितों को साधने का प्रयास किया है। ब्रिक्स, जी-20 और क्राइ जैसे मंचों पर भारत की सक्रियता यह संकेत देती है कि नई दिल्ली स्वयं को केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहती है। लेकिन किसी भी सरकार का निष्पक्ष मूल्यांकन केवल उपलब्धियों की सूची से नहीं होता। आर्थिक मोर्चे पर अभी भी अनेक प्रश्न मौजूद हैं। विनिर्माण क्षेत्र को अपेक्षित गति नहीं मिल सकी है। उच्च तकनीक उत्पादन में चीन जैसी प्रतिस्पर्धी ताकतों से मुकाबला आसान नहीं है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं और भू-राजनीतिक तनाव भी भारत की महत्वाकांक्षाओं के सामने चुनौतियां खड़ी करते हैं। फिर भी यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मोदी सरकार के बारह वर्षों का सबसे बड़ा राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव भारत की राष्ट्रीय सोच में दिखाई देता है। अब बहस केवल सत्ता परिवर्तन की नहीं, बल्कि उस परिवर्तन की है जो स्वयं को आत्मनिर्भर, सुरक्षित, तकनीकी रूप से सक्षम और वैश्विक मंच पर निर्णायक भूमिका निभाने योग्य राष्ट्र के रूप में देखना चाहता है। इतिहास मोदी सरकार का अंतिम मूल्यांकन इसी कसौटी पर करेगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और तकनीकी शक्ति के ये दावे भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था की वास्तविक ताकत को कितनी गहराई तक बदल सके। उपलब्धियों की यह कहानी प्रभावशाली अवश्य है, लेकिन इसकी अंतिम सफलता आने वाले वर्षों के परिणामों से तय होगी। (जारी..)

यदि पूर्वाग्रहों और राजनीतिक अग्रहों से परे हटकर मूल्यांकन किया जाए तो यह स्वीकार करना होगा कि मोदी सरकार ने भारत की राष्ट्रीय आकांक्षाओं को एक नया स्वर दिया है। आजादी के बाद अनेक सरकारें आईं और गईं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक अवसरचना और आत्मनिर्भरता को जिस स्पष्टता और प्राथमिकता के साथ पिछले बारह वर्षों में केंद्र में रखा गया, वैसा

उदाहरण पहले कम ही दिखाई देता है। मोदी सरकार की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में रक्षा क्षेत्र का परिवर्तन प्रमुख है। एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में गिना जाता था। आज भी आयात पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन तस्वीर बदल रही है। वर्ष 2014-15 में भारत का रक्षा निर्यात एक हजार करोड़ रुपये से भी कम था। 2024-25 तक यह बढ़कर 23,622 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। अर्थात् एक दशक में लगभग चौबीस गुना वृद्धि। इसी अवधि में रक्षा उत्पादन भी लगभग 46 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 1.54 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। भारत अब सौ से अधिक देशों को रक्षा सामग्री निर्यात कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल, आर्टिलरी सिस्टम, रडार, बुलेटप्रूफ जैकेट, सैन्य वाहन, गोला-बारूद, डोर्नियर विमान के पुर्जे और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती क्षमता का परिचय दे रही हैं। यह परिवर्तन केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जो देश हथियार बेचता है, उसकी अंतरराष्ट्रीय हैसियत स्वाभाविक रूप से बदलती है।

हालांकि तस्वीर का दूसरा पक्ष भी है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़े बताते हैं कि भारत का वैश्विक हथियार आयात पहले की तुलना में कम हुआ है, लेकिन रूस, फ्रांस, अमेरिका और इजरायल जैसे देशों पर निर्भरता अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। जेट इंजन, उन्नत लड़ाकू विमान तकनीक, कुछ अत्याधुनिक सेंसर और लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में भारत को अभी लंबी दूरी तय

पर्यटन सीजन पर होगा असर
पेट्रोल के बाद जेट फ्यूल के दाम बढ़ें
अब हवाई सफर भी पड़ेगा महंगा

नई दिल्ली, एजेंसी
पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के बाद अब विमानन ईंधन (एविएशन टर्बाइन फ्यूल-एटीएफ) भी महंगा हो गया है। इसकी कीमत में करीब 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही सरकार समर्थित नई प्राइस स्टेबिलाइजेशन स्कीम लागू की गई है, जिससे तहत एयरलाइंस तीन साल तक के लिए ईंधन की कीमत तय कर सकती हैं।

नई व्यवस्था के तहत स्कीम में शामिल होने वाली एयरलाइंस को अब एटीएफ के लिए लगभग 115 रुपये प्रति लीटर चुकाने होंगे। इससे पहले यह कीमत 104.93 रुपये प्रति लीटर थी। हालांकि यह दर अभी भी बाजार आधारित कीमतों से कम है। जो एयरलाइंस इस योजना में शामिल नहीं होंगी, उन्हें मौजूदा बाजार दर पर ईंधन खरीदना होगा, जो फिलहाल करीब 142 रुपये प्रति लीटर है। विमानन क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि एयरलाइंस की कुल परिचालन लागत में ईंधन का हिस्सा 35 से 40 प्रतिशत तक होता है। ऐसे में जेट फ्यूल की कीमत में 10 प्रतिशत वृद्धि का सीधा असर टिकट दरों पर पड़ना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि किराए में वृद्धि सभी रूटों पर एक समान नहीं होगी।



शामिल नहीं होंगी, उन्हें मौजूदा बाजार दर पर ईंधन खरीदना होगा, जो फिलहाल करीब 142 रुपये प्रति लीटर है। विमानन क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि एयरलाइंस की कुल परिचालन लागत में ईंधन का हिस्सा 35 से 40 प्रतिशत तक होता है। ऐसे में जेट फ्यूल की कीमत में 10 प्रतिशत वृद्धि का सीधा असर टिकट दरों पर पड़ना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि किराए में वृद्धि सभी रूटों पर एक समान नहीं होगी।

होर्मुज पर भीषण जंग... अपाचे हेलीकॉप्टर गिराए जाने का बदला

अमेरिका ने ईरान के रडार ठिकानों पर बरसाए बम, ईरान का भी पलटवार

वॉशिंगटन/तेहरान, एजेंसी

एक तरफ दुनिया जंग के खात्मे का इंतजार कर रही है वहीं होर्मुज स्ट्रेट में तनाव अब सीधे अमेरिकी-ईरानी सैन्य टकराव में बदल गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और निगरानी रडार ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने पुष्टि की है कि यह कार्रवाई एक अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर के गिराए जाने के जवाब में की गई। अमेरिकी हमले मुख्य रूप से होर्मुज स्ट्रेट के आसपास स्थित ईरानी सैन्य प्रतिष्ठानों पर केंद्रित रहे। अमेरिकी सेना का दावा है कि इन ठिकानों का उपयोग ड्रोन संचालन, समुद्री निगरानी और वायु रक्षा के लिए किया जा रहा था।

ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरानी रिबोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा किया है। अधिकांश हमलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है।

ताजा टकराव की शुरुआत तब हुई जब होर्मुज के पास एक अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर गिर गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके लिए ईरान को

जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले



जिम्मेदार ठहराते हुए आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया। इसके बाद अमेरिकी लड़ाकू विमानों और मिसाइलों ने ईरानी सैन्य ढांचों को निशाना बनाया। ईरान की ओर से जारी बयान में चेतावनी दी गई है कि यदि अमेरिका की सैन्य गतिविधियां जारी रहें तो और अधिक कड़ी जवाबी

कार्रवाई की जाएगी। हमलों के बाद बहरीन में मिसाइल अलर्ट सायरन बजाए गए और गृह मंत्रालय ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। बहरीन फारस की खाड़ी में स्थित एक महत्वपूर्ण द्वीपीय देश है, जहां अमेरिकी नौसेना का फिफ्थ फ्लीट तैनात है।

भोपाल में वरिष्ठ नेताओं ने शुरू किया उपवास मीनाक्षी मामले में चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस

भोपाल/नईदिल्ली. दोपहर मेट्रो
मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद विवाद गहरा गया है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर रहा है। प्रतिनिधिमंडल में केंसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला, सचिन पायलट, भूपेश बघेल, दीपा दासमुंशी, विवेक तन्खा, मीनाक्षी



नटराजन, मोहम्मद अली खान और उमर होडा शामिल हैं। इधर, भोपाल में कांग्रेस के कार्यकर्ता बुधवार को मुख्य निर्वाचन

पदाधिकारी (सीईओ) दफ्तर पहुंचे। गेट बंद मिलने पर उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गणवेश दफ्तर के बाहर गेट पर टांग दी और लौट गए। भोपाल में कांग्रेस ने उपवास शुरू कर दिया है। सामूहिक उपवास में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पीसीएस चौफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कांग्रेस के तमाम विधायक मौजूद हैं।

पांड्या अफगानिस्तान सीरीज से बाहर

मुंबई। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ताजा चोट के कारण अफगानिस्तान से तीन मैचों की पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। पांड्या को बंगलूरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस आकलन के दौरान क्वाड्रिसेप्स (जांच की मांसपेशी) में खिंचाव आ गया था।



इंदौर. एजेंसी
इंदौर में लोकायुक्त पुलिस ने आज महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक लक्ष्मी नारायण के डेवाल के ठिकानों पर छापा मारा। लोकायुक्त को शुरुआती जांच में उनके पास आय से अधिक संपत्ति होने के

संयुक्त संचालक के यहां मिली 9.5 करोड़ की संपत्ति

प्रमाण मिले हैं। इस पर कार्रवाई की गई है और उनके ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। सत्यापन में प्रथम दृष्टया आय से अधिक संपत्ति अर्जित करना सामने आने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। इसके बाद आज छापाकार कार्रवाई शुरू की गई। उनके स्कीम नंबर 103 में पांच मजिला मकान पर छापा मारा गया।

पाक का अफगान पर हमला, 13 की मौत

इस्लामाबाद. एजेंसी
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाके में हवाई हमले किए हैं, जिसमें 11 बच्चों सहित 13 लोगों की मौत हो गई है और 14 लोग बुरी तरह से घायल हैं। अफगानिस्तान ने दावा किया है कि पाक ने उसती सीमा में घुसकर हमले किए हैं, जिसमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों की जान चली गई है। पाकिस्तान की तरफ से ये हमले अफगानिस्तान के कुनार, खोस्त और पकिंका प्रांतों के रिहायशी इलाकों में किया गया है।

उनका सुपर स्टोर और जिम भी है। उनके इन सभी ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान दस्तावेजों, संपत्तियों और निवेश से जुड़े रिकॉर्ड खंगले जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच के अनुसार संयुक्त संचालक लक्ष्मी नारायण कंडेवाल की 2.5 करोड़ की आय है और उनके पास 9.5 करोड़ की संपत्ति है।

46 लाख रुपए देने का आदेश बेटियों की शिक्षा का खर्च उठाना पिता की जिम्मेदारी - हाईकोर्ट

जबलपुर, एजेंसी
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंदसौर में नर्सिंग कॉलेज चलाने वाली सोसायटी के अध्यक्ष को आदेश दिया है कि वह अपनी 2 बेटियों की उच्च शिक्षा पूरी करवाने के लिए 46.26 लाख रुपये अदा करें। कोर्ट ने साफ किया कि बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाना पिता की जिम्मेदारी है, यह केवल बुनियादी जरूरतों तक सीमित नहीं है। यह फैसला तब आया, जब मां और बेटियों ने यह दलील दी कि पहले का गुजारा भत्ता का आदेश कॉलेज की फीस के लिए पर्याप्त नहीं था। बेटियों में से एक किर्गिस्तान में मेडिसिन की पढ़ाई कर रही है, जबकि दूसरी जयपुर की मणिपाल यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रही है। हालांकि, पिता ने पैसों की तंगी का दावा किया था, लेकिन उनके



वित्तीय रिकॉर्ड कुछ और ही दर्शा रहे थे। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बेटियों की शिक्षा के खर्च से बचना गलत है और पिता को 4 महीने के भीतर यह रकम चुकाने का निर्देश दिया। यदि वे इसमें देरी करते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त ब्याज भी देना पड़ेगा। इससे पहले पारिवारिक न्यायालय ने मां के लिए 6,000 रुपये और हर बेटे के लिए 3,000 रुपये का मासिक गुजारा भत्ता तय किया था। मगर, कॉलेज की फीस के मुकाबले यह रकम बहुत कम पड़ रही थी।

शिफ्ट चेंज के दौरान हुई घटना जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में ग्रेनेड फटने से दो जवानों की मौत

जम्मू, एजेंसी
जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां एलओसी से उरी सेक्टर में एक आर्मी कैम्प में हेंड ग्रेनेड फटने से सेना के दो जवानों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने इस घटना की पुष्टि की है। पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले बताया है कि यह भयावह हादसा उरी सेक्टर के कमलकोट इलाके में स्थित सेना के एक कैम्प में हुआ। जानकारी के अनुसार कैम्प में जवानों के बीच रोजाना की तरह हथियारों और सैन्य उपकरणों की शिफ्ट चेंज के दौरान सौंपने की प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान एक हेंड ग्रेनेड अचानक फट गया। अचानक हुए जोरदार धमाके की चपेट में आने से



ड्यूटी पर तैनात दो जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायल जवानों को तुरंत सेना के 92 बेस हॉस्पिटल ले जाया गया। हालांकि अस्पताल लाते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सेना ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। इस बीच, श्रीनगर स्थित डिफेंस पीआरओ ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है कि वे संबंधित अधिकारियों से घटना की पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद ही इस पर कोई आधिकारिक और विस्तृत टिप्पणी करेंगे।

सुविधाएं कुछ भी नहीं, यात्रियों पर बड़ा अतिरिक्त बोझ

स्पेशल ट्रेन के नाम पर यात्रियों से वसूला जा रहा अधिक किराया

भोपाल मंडल से प्रतिदिन गुजरती हैं 40 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

रेलवे की स्पेशल ट्रेनों को लेकर एक बार फिर किराया व्यवस्था सवालों के घेरे में है। यात्रियों का आरोप है कि कई स्पेशल ट्रेनों में सामान्य ट्रेनों जैसी ही सुविधाएं होने के बावजूद उनसे 20 से 25 प्रतिशत तक अधिक किराया वसूला जा रहा है। ट्रेन नंबर के आगे '0' जोड़कर इन्हें स्पेशल श्रेणी में संचालित किया जाता है, जबकि कोच, सीट क्षमता और अधिकांश सुविधाएं सामान्य ट्रेनों के समान रहती हैं। भोपाल मंडल

से प्रतिदिन लगभग 40 स्पेशल ट्रेनें गुजर रही हैं और इनमें अधिकांश ट्रेनों में यात्रियों की अच्छी-खासी भीड़ बनी रहती है।

तीन महीने में 18 हजार से ज्यादा फेरे

रेलवे द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 15 अप्रैल से 15 जुलाई 2026 के बीच 908 समर स्पेशल ट्रेनों के 18,262 ट्रिप संचालित किए जा रहे हैं। यदि प्रति ट्रिप औसतन 1.25 लाख रुपये अतिरिक्त किराया वसूली का अनुमान लगाया जाए तो रेलवे को इस अवधि में



करीब 2,284 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है। भोपाल रेल मंडल से गुजरने वाली स्पेशल ट्रेनों से भी सालाना करोड़ों रुपये की अतिरिक्त कमाई होने का अनुमान है।

भोपाल-पुणे मार्ग पर किराए में बड़ा अंतर

उदाहरण के तौर पर भोपाल से पुणे जाने वाले यात्रियों के सामने यदि सामान्य और स्पेशल ट्रेन दोनों विकल्प हों तो किराए में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। सामान्य सुपरफास्ट ट्रेन में सेकंड एसी का किराया 1810 रुपये है, जबकि स्पेशल ट्रेन में यही किराया 2185 रुपये तक पहुंच जाता है। यानी यात्री को लगभग 375 रुपये अधिक चुकाने पड़ते हैं, जबकि सुविधाओं में कोई विशेष अंतर नहीं होता।

लखनऊ मार्ग पर भी समान स्थिति

जानकारी के अनुसार भोपाल-प्रतापगढ़ एक्सप्रेस और पुणे-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन की तुलना में भी सेकंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर श्रेणी में 19 से 26 प्रतिशत तक अधिक किराया देखा गया। वहीं यात्रा अवधि भी स्पेशल ट्रेन में कुछ अधिक बताई जा रही है।

विशेष ट्रेनों का संचालन यात्रियों की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए जरूरी है, लेकिन लंबे समय से यात्रियों के मन में यह सवाल बना हुआ है कि जब कई स्पेशल ट्रेनों का रूट, दूरी और यात्रा समय सामान्य ट्रेनों जैसा ही है, तो उनसे अधिक किराया क्यों लिया जाता है। ज्यादा किराया लेना बंद किया जाए।

- कमलेश सेन, सदस्य, सलाहकार समिति पश्चिम मध्य रेल मंडल भोपाल

अगले सप्ताह होगी समिति की बैठक, बस संचालकों के दो प्रतिनिधि भी रहेंगे

बढ़ने जा रहा है बसों का किराया 12 से 20 प्रतिशत तक होगी वृद्धि!

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

पांच वर्ष बाद सार्वजनिक यात्री बसों के किराये में बढ़ाव की तैयारी है। इसे लेकर अगले सप्ताह किराया निर्धारण समिति की बैठक होने जा रही है। इसमें बस किराये से संबंधित प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। बैठक में नियमानुसार बस संचालकों के दो प्रतिनिधि भी सम्मिलित रहेंगे, जिससे निर्णय के बाद में किसी तरह की आपत्ति या विरोध न होने पाए।

किराया निर्धारण समिति का प्रशासनिक दांचा

बता दें कि वर्ष 2010 में गठित किराया निर्धारण समिति में प्रमुख सचिव (परिवहन), आर्थिक सलाहकार वित्त, आयुक्त वाणिज्यिक कर और परिवहन आयुक्त, आयुक्त भोपाल संभाग, प्रबंध संचालक राज्य परिवहन उपक्रम और परिवहन आयुक्त द्वारा नामांकित दो बस ऑपरेटर प्रतिनिधि शामिल हैं।

सरकार जुलाई में इंद्रौर से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा प्रारंभ करने जा रही है। इसमें निजी बसों को अनुबंधित कर चलाया जाना है। इसमें निगरानी ऐसी रहेगी कि बस संचालक क्षमता से अधिक यात्री नहीं बैठा सकेंगे न ही किराया में चोरी हो सकेगी। इस कारण वे किराया बढ़ाने की मांग उठा रहे हैं।



प्रस्तावित किराये का गणित

अभी बसों का किराया पहले किलोमीटर के लिए सात रुपये और फिर 1.40 रुपये प्रति किलोमीटर है। इसे प्रति किलोमीटर 1.50 रुपये तक किया जा सकता है। बस संचालकों के प्रतिनिधियों ने इस संबंध में सोमवार को परिवहन विभाग के अधिकारियों से भेंट की थी। यात्री बसों का किराया इसके पहले वर्ष 2021 में बढ़ाया गया था। बस संचालकों का तर्क है कि इसके बाद से डीजल, टैक्स व अन्य खर्च बढ़े हैं, लेकिन किराया नहीं बढ़ा। वे इसे दो रुपये प्रति किलोमीटर करने की मांग कर रहे हैं।

ऑटो ड्राइवर, बोले- किराया बढ़े, पेट्रोल-सीएनजी बढ़ने का विरोध

पेट्रोल-डीजल और सीएनजी की बढ़ी कीमतों के बाद अब टैक्स-ऑटो चालक किराया बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। भोपाल में भी यह मांग उठ रही है। उनका कहना था कि ईंधन इतना महंगा हो गया है कि अंडरवियर खरीदने तक के रूप नहीं है। इसलिए सरकार किराया बढ़ाए। ऑटो संगठन के अध्यक्ष संजु अहिरवार ने बताया, यदि सीएनजी वाला ऑटो है तो उसमें एक दिन में 500 रुपये की गैस भरवाते हैं। इसके बदले 1200 रुपये का धंधा होता है। बाकी बचे 700 रुपये में से बचत, ऑटो की किश्त भी शामिल है। मुश्किल से 500 रुपये नहीं बचते हैं। इसलिए ऑटो का किराया बढ़ाने की मांग सरकार से की है। चालकों का कहना था कि ऑटो की किश्त, ईंधन खर्च, वाहन रखरखाव और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते-निभाते उनकी आर्थिक हालत खराब हो चुकी है। चालकों ने कहा कि इतनी महंगाई में परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन ऑटो किराए में लंबे समय से कोई संशोधन नहीं किया गया।

गोदरमऊ जिनालय में महामस्तकाभिषेक



भोपाल। गोदरमऊ जिनालय में भगवान मुनिसुव्रतनाथनाथ स्वामी का महामस्तकाभिषेक संपन्न हुआ। इसमें श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भक्ति के साथ हिस्सा लिया। इस जिनालय में प्रतिष्ठा का एक वर्ष पूरा हुआ है। आचार्य विद्या समय सागर महाराज के शिष्य निर्यापक मुनि संभव सागर महाराज के ससंग सानिध्य में पूजा अर्चना अनुष्ठान हुए।

चलती ट्रेन में अपराध की जांच से समन्वय तक की बारीकियां सीखेंगे जीआरपी के जवान

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

22 जून तक चलने वाले इस प्रशिक्षण का PTRI में हुआ उद्घाटन जीआरपी में पदस्थ होने वाले पुलिसकर्मियों के लिए 15 दिवसीय रिफ्रेशर व ओरियंटेशन कोर्स सोमवार से शुरू हो गया है। 22 जून तक चलने वाले इस प्रशिक्षण का उद्घाटन पीटीआरआई में स्पेशल डीजी सीआईडी पंकज श्रीवास्तव और एडीजी रेल राजाबाबू सिंह ने किया। इसका मकसद जीआरपी में जिला पुलिस से आने वाले

पुलिसकर्मियों को रेलवे पुलिसिंग की विशेष चुनौतियों से परिचित कराना है। इसके लिए जीआरपी मुख्यालय में हाल ही में निर्णय लिया है कि जिला पुलिस से जीआरपी में आने वाले पुलिसकर्मियों को सीधे फील्ड में नहीं भेजा जाएगा।

उन्हें पहले यह विशेष प्रशिक्षण लेना होगा। कोर्स पूरा करने के बाद ही उनकी फील्ड पोस्टिंग की जाएगी। अफसरों का मानना है कि जिला पुलिस और जीआरपी की कार्यप्रणाली में बड़ा अंतर है, जिसके

कारण कई बार नए स्टाफ को रेलवे पुलिसिंग की व्यावहारिक चुनौतियों को समझने में समय लगता है।

एडीजी रेल राजाबाबू सिंह ने बताया कि रेलवे पुलिसिंग सामान्य पुलिसिंग से अलग व चुनौतीपूर्ण है। ट्रेन में चोरी या लूट की वारदात का पता यात्रियों को नौद खलने या अगला स्टेशन आने पर चलता है। ऐसे में अपराध का सटीक स्थान, समय और अधिकार क्षेत्र तय करना जांच का मुश्किल हिस्सा होता है।

सेवा सदन ने लौटाई मुस्कान

कृत्रिम नेत्र प्रत्यारोपण से बदली दो युवाओं की जिंदगी

हीन भावना और उपहास से मिला छुटकारा, तय हुए दोनों के वैवाहिक रिश्ते

संतनगर, दोपहर मेट्रो।

कई लोगों के लिए आंखों की समस्या केवल एक चिकित्सकीय परेशानी होती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह जीवनभर का भावनात्मक संघर्ष बन जाती है। विदिशा की 29 वर्षीय रागिनी और भोपाल के 28 वर्षीय विकास (परिवर्तित नाम) भी लंबे समय से एक-एक आंख की गंभीर विकृति के कारण ऐसा ही दर्श झेल रहे थे। इसकी वजह से उन्हें न केवल समाज में उपहास और हीन भावना का शिकार होना पड़ता था, बल्कि वैवाहिक रिश्तों की बात चलने पर भी हमेशा रिजेक्शन (अस्वीकृति) का सामना करना पड़ता था।

मानसिक और सामाजिक रूप से संघर्ष कर रहे इन दोनों युवाओं को भोपाल के सेवा सदन आई हॉस्पिटल में एक नई उम्मीद मिली। अस्पताल में उपलब्ध अत्याधुनिक कृत्रिम नेत्र (प्रोस्थेटिक आई) तकनीक से दोनों का सफल उपचार किया गया। शुरुआत में मरीजों और उनके परिजनों ने अस्पताल में पहले से इलाज करा चुके अन्य लोगों के सकारात्मक परिणाम देखे, उनसे बातचीत की और फिर आगे बढ़ने का फैसला लिया।

सूने मकान में चोरों ने जेवरात उड़ाए

भोपाल। गांधी नगर में स्थित एक सूने मकान में चोरों ने संध लगा दी। बदमाश ग्लिल काटकर अंदर से सोना-चांदी के गहने सहित लाखों का सामान चुरा ले गए। घर मालिक विदेश में हैं। इस कारण उन्होंने नौकरानी को थाने भेजकर प्रकरण दर्ज कराया। पुलिस के अनुसार वारदात द्वारका धाम कॉलोनी में हुई है। यहां गिरिशा चंद्रा श्रीवास्तव रहते हैं। घर की देखरेख का काम शीला अहिरवार पति बृजेश अहिरवार उम्र 38 साल करती हैं। वे ईटखेड़ी में स्थित ग्राम चांदपुर में रहती हैं। चोरी की जानकारी शीला अहिरवार को ही सबसे पहले मिली थी। चोर दो कमरों में लगी ग्लिल को काटकर भीतर घुसे थे।

विशेषज्ञों की टीम ने दिया नया रूप

अस्पताल की वरिष्ठ चिकित्सक एवं ऑक्ज्यूलोप्लास्टी विशेषज्ञ डॉ. रोहिनी गर्डे ने दोनों मरीजों को विस्तार से परामर्श देकर आश्वस्त किया कि उपचार के बाद उनका चेहरा बिल्कुल सामान्य दिखेगा। इस भरोसे के बाद जयपुर के अनुभवी ऑक्ज्यूलिस्ट गोपाल पाटनकर के सहयोग से दोनों का इलाज शुरू हुआ।

शुरू होने जा रहा नया जीवन

सफल प्रत्यारोपण के बाद दोनों मरीजों के चेहरे का स्वरूप पूरी तरह सामान्य हो गया है और कोई भी यह आसानी से नहीं पहचान सकता कि उनकी आंख कृत्रिम है। इस बदलाव से दोनों परिवारों में खुशी का माहौल है। सबसे सुखद बात यह है कि जिन दोनों युवाओं को पहले विवाह के लिए बार-बार अपमानित होना पड़ता था, आज उन दोनों के वैवाहिक रिश्ते तय हो चुके हैं।

टाइगर फाउंडेशन समिति की बैठक में क्षेत्रीय आयोजनों के निर्देश

वन्यजीव संरक्षण: मप्र में होंगे चरवाहा सम्मेलन

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

वन्यजीवों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये मप्र में चरवाहा सम्मेलन आयोजित किये जाएंगे। टाइगर फाउंडेशन समिति की बैठक में यह निर्देश वन विभाग के प्रमुख सचिव संदीप यादव ने दिये हैं। मंत्रालय में आयोजित इस दौरान 22वीं शासी निकाय की बैठक में वन्य-जीव संरक्षण, आवास विकास एवं ब्लैकबक कैचर ऑपरेशन सहित विभिन्न कार्यों के लिये लगभग 22.79 करोड़ रुपये के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं।

इसके पहले यादव ने वन्य-जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये जागरूकता बढ़ाने के लिये क्षेत्रीय स्तर पर चरवाहा सम्मेलन आयोजित करने पर बल दिया गया। हालांकि इसके लेकर कोई कार्ययोजना सामने नहीं आई है। बावजूद इसके अधिकारियों का कहना है कि वन्यजीव संरक्षण को जनआंदोलन बनाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में क्षेत्रीय स्तर पर चरवाहा सम्मेलन आयोजित कर



इस पर खर्च होंगे 22.79 करोड़

संरक्षित क्षेत्रों, वन मण्डलों में वन्य-जीव संरक्षण, आवास विकास, मानव वन्य-जीव संघर्ष न्यूनीकरण, अनुसंधान, अध्ययन, जागरूकता एवं क्षमता संवर्धन के साथ ब्लैकबक कैचर ऑपरेशन से संबंधित कार्यों के लिये लगभग 22.79 करोड़ की राशि के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं। इसके साथ ही समिति के वर्ष 2026-27 के वार्षिक कार्य-योजना (एपीओ) का भी अनुमोदन किया गया। बैठक में टाइगर फाउंडेशन समिति की 21वीं बैठक का अनुमोदन किया गया।

ग्रामीण समुदायों को संरक्षण गतिविधियों से जोड़ने के प्रयास किये जाएंगे। बैठक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख शुभ्रंजन सेन, प्रधान मुख्य वन

संरक्षक वन्य-जीव डॉ. समीता राजौरा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

मेट्रो एंकर

मानव संग्रहालय में हुई 30 दिवसीय कार्यशाला समापन आज

रंगमंच में बच्चों ने सीखा मोबाइल से दूरी बनाना

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 30 दिवसीय प्रोडक्शन ओरिएंटेड चिल्ड्रन्स थिएटर वर्कशॉप ने बच्चों को मोबाइल की दुनिया से निकालकर रंगमंच, कला और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने का काम किया है।

कार्यशाला का समापन आज संग्रहालय परिसर स्थित वीथि संकुल सभागार में नाटक 'मोबाइल का जाल, जी का जंजाल' की प्रस्तुति के साथ होगा। शाम 6 बजे होने वाले इस मंचन में बाल कलाकार मोबाइल के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को



अभिनय के माध्यम से दर्शकों के सामने रखेंगे। एक माह तक चली इस कार्यशाला में बच्चों को अभिनय, संवाद, शारीरिक

अभिव्यक्ति, स्वराभिनय, लोककला, गीत-संगीत और नृत्य का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला के दौरान बच्चों ने मोबाइल से दूरी

कांग्रेस का नारी सम्मान सिर्फ दिखावा - आशीष अग्रवाल

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

राज्यसभा चनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी का परचा निरस्त होने पर प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल के प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि तेलंगाना में कांग्रेस नेता कुंभम शिवकुमार रेड्डी पर एक महिला कार्यकर्ता द्वारा शादी का झांसा देकर शोषण, ब्लैकमेल करने और धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। शिकायत और प्रकरण दर्ज होने के बाद तत्कालीन प्रभारी मीनाक्षी नटराजन की भूमिका को लेकर भी प्रश्न उठे और उनका नाम भी अपराध पंजीयन में सामने आया। गंभीर बात

यह है कि महिला से जुड़े इस गंभीर प्रकरण का उल्लेख राज्यसभा नामांकन पत्र में नहीं किया गया। जब तथ्य सामने आने पर नामांकन निरस्त हुआ, तब कांग्रेस लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने लगी। यह रवैया कांग्रेस के दोहरे चरित्र और महिला सम्मान के प्रति उसकी वास्तविक सोच को उजागर करता है। श्री अग्रवाल ने इस विषय को लेकर कई सवाल भी उठाए हैं और उनका कहना है कि कांग्रेस को देश की महिलाओं और जनता को इनका जवाब देना चाहिए। क्या महिला कार्यकर्ता को शिकायत को गंभीरता से लिया गया और आरोपों की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

भांजे ने की मामी की गला घोट कर हत्या

भोपाल। नजीराबाद इलाके में एक बुजुर्ग महिला का अपहरण कर उसकी गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद उसके चांदी के भारी भरकम कड़े निकालने के लिए आरोपी ने दोनों पैर कुल्हाड़ी से काट दिए थे। पुलिस ने इस मामले में सोमवार को हत्या, अपहरण और लूटपाट का प्रकरण दर्ज किया। 60 वर्षीय बादाम बाई मृतका के अपहरण, हत्या और लूट के इस मामले में पुलिस ने मृतका के 35 वर्षीय भांजा दामाद जसमन गुर्जर को गिरफ्तार किया है।

बनाकर अपनी रचनात्मक क्षमताओं को निखारा और मंचीय प्रस्तुति की बारीकियां सीखीं। संग्रहालय निदेशक प्रो. अमिताभ पांडे के अनुसार इस पहले से बच्चों में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक जागरूकता का विकास हुआ है। कार्यशाला में अभिनेत्री वाणी त्रिपाठी टिककर, रंग निदेशक जितेंद्र सिंह गुर्जर और कथक विशेषज्ञ संगीता श्रीवास्तव सहित कई विशेषज्ञों ने बच्चों का मार्गदर्शन किया। नाटक की रचना, गीत और निर्देशन संजय श्रीवास्तव ने किया है। प्रस्तुति के माध्यम से संतुलित जीवनशैली, पारिवारिक संवाद और सामूहिक गतिविधियों के महत्व का संदेश दिया जाएगा।

गुफा मंदिर में आयोजित प्रार्थना कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर बुधवार को लालघाटी स्थित गुफा मंदिर में विशेष हनुमान चालीसा एवं प्रार्थना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल हुए और देश की प्रगति, समृद्धि तथा जनकल्याण के लिए प्रार्थना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ से मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर हो गया। उन्होंने ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और जनसेवा के क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वस्थ, दीर्घायु और सफल जीवन की कामना करते हुए राष्ट्र के उज्वल भविष्य के लिए प्रार्थना की। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं ने भी देश की उन्नति और खुशहाली के लिए मंगलकामनाएं कीं।



विदेशी मेहमानों ने इंदौर में की हेरिटेज वॉक, जाना होलकरकालीन इतिहास

इंदौर। इंदौर में चल रहे ब्रिक्स कृषि सम्मेलन में भाग लेने आए अलग-अलग देशों से आए प्रतिनिधियों और कृषि विशेषज्ञों के लिए बुधवार की सुबह कुछ खास थी। उनके लिए एक बार फिर शहर के ऐतिहासिक स्थलों का इतिहास जीवंत किया गया। राजवाड़ा पैलेस में पुगने समय में लगने वाले दरबार की तरह हरकारों की गुंज सुनाई दी और शास्त्रीय संगीत की स्वर-लहरियां गुंजीं। ब्रिक्स सम्मेलन में जर्मनी, इथियोपिया, इंडोनेशिया सहित 20 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। उनके लिए सुबह हेरिटेज वॉक आयोजित की गई। पहले यह वॉक बोलिया सरकार छात्रों से होना थी, लेकिन उसके बजाय मेहमान साढ़े छह बजे सीधे राजवाड़ा पहुंचे। यहां उनके लिए लाल मेज लगाई गई थी। इतिहासकार जयर अंसारी ने इंदौर की महारानी देवी अहिल्या के शासनकाल के अलावा होलकरकाल से जुड़े इतिहास के तथ्य बताए। राजवाड़ा में जब दरबार लगाता था, तब दूसरे राज्यों के राजाओं को किस तरह हरकार देकर सम्मानित किया जाता था, इसकी प्रस्तुति भी दी गई। इसके बाद राजवाड़ा पर संगीत और नृत्य की प्रस्तुति भी कलाकारों ने दी।

सिंहस्थ-2028 की तैयारियों को मिली नई रफतार

491 करोड़ के 17 नए कार्य मंजूर, 16,910 करोड़ की विकास योजनाओं की हुई समीक्षा

भोपाल, दोपहर मेट्रो

सिंहस्थ-2028 के भव्य, दिव्य और सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर मध्यप्रदेश सरकार ने तैयारियों को और गति देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-मंडलीय समिति की छठवीं बैठक में 491.66 करोड़ रुपये की लागत के 17 नए विकास एवं निर्माण कार्यों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में उज्जैन सहित आसपास के सात जिलों में प्रगति पर चल रहे 16 हजार 910 करोड़ रुपये से अधिक लागत के 148 विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा भी की गई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधा, बेहतर आवागमन, पर्याप्त पेयजल, सुरक्षित स्नान घाट, उदरने की व्यवस्था तथा आधुनिक सुरक्षा प्रबंधन से जुड़े सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे किए जाएं। उन्होंने भीड़ प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, चिकित्सा सुविधाओं और तकनीक आधारित सुरक्षा व्यवस्था के लिए अभी से माइक्रो प्लानिंग शुरू करने पर जोर दिया।



उज्जैन में सड़क और पुल निर्माण को मिली प्राथमिकता

बैठक में उज्जैन क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई। शनि मंदिर से प्रशांति धाम चौराहा मार्ग तक 30 करोड़ रुपये की लागत से पुल और एप्रोच रोड का निर्माण होगा। तपोभूमि से पिपलियाराघो पंचक्रोशी मार्ग पर कान्हे नदी पर 12 करोड़ रुपये की लागत से नया समानांतर पुल बनाया जाएगा। इसके अलावा तपोभूमि से गंगेड़ी होते हुए राघोपलव्या

तक 5.5 किलोमीटर लंबी नई दो लेन सड़क, देवास रोड से लालपुर होते हुए गरोठ मार्ग तक फोरलेन पंचक्रोशी मार्ग, लेकोड़ा से टनकारिया रेलवे स्टेशन तक नई सड़क और महाकाल थाना से चौबीस खंबा मार्ग तक नई सड़क निर्माण को भी मंजूरी दी गई। कुशाभाऊ ठाकरे मार्ग से छोटी रफतार तक सड़क चौड़ीकरण कार्य भी स्वीकृत परियोजनाओं में शामिल है।

ऑकारेश्वर में बनेगा हेलीपैड और आधुनिक अस्पताल

बैठक में ऑकारेश्वर मंदिर और आसपास के क्षेत्र के विकास को विशेष प्राथमिकता दी गई। ऑकारेश्वर मंदिर परिसर के विकास, सीसी रोड निर्माण, रेलवे आरओबी, मल्टीलेवल पार्किंग, फूड कोर्ट, प्रशासनिक भवन, अस्पताल और स्टाफ क्वार्टर सहित अनेक परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ऑकारेश्वर में सर्वसुविधायुक्त अस्पताल और हेलीपैड निर्माण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदा या आपातकालीन स्थिति में एयर एम्बुलेंस सेवा और त्वरित राहत कार्यों के लिए यह सुविधाएं अत्यंत उपयोगी साबित होंगी।

ऑकारेश्वर-बड़वाह क्षेत्र के लिए बनेगा पृथक प्राधिकरण

मुख्यमंत्री ने बड़वाह, ऑकारेश्वर और खेडीघाट क्षेत्र के समग्र विकास के लिए पृथक प्राधिकरण गठित करने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि इससे खंडवा और खरगोन जिलों में चल रहे विकास कार्यों का बेहतर समन्वय सुनिश्चित होगा और परियोजनाएं समय पर पूर्ण हो सकेंगी। साथ ही ऑकारेश्वर के लिए वैकल्पिक मार्ग विकसित करने की योजना पर भी कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि उज्जैन में शिप्रा नदी के घाटों का निर्माण चरणबद्ध ढंग से पूरा किया जाए तथा पार्किंग और पहुंच मार्गों का विकास समानांतर रूप से किया जाए। उन्होंने घाटों के प्रबंधन में स्थानीय आश्रमों और गुरुकुलों को जोड़ने का सुझाव दिया, जिससे धार्मिक संस्थानों को सहयोग मिलेगा और घाटों का दीर्घकालिक उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।

जबलपुर में रेत उत्खनन-परिवहन पर शिकंजा

पांच महीने में लगा 14.60 करोड़ रुपये का जुर्माना



जबलपुर, दोपहर मेट्रो

नर्मदा समेत हिन्द नदी और अन्य नदियों में रेत उत्खनन धमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी पोक्लेन की मदद से नर्मदा से रेत निकाली जा रही है तो कहीं मोटर लगी नाव से। इतना ही नहीं कई रेत माफिया, नदी में मशीन डालकर, पाइप लाइन बिछाकर अवैध रूप से रेत निकाल रहे हैं। बावजूद इसके जिला प्रशासन अब तक इन रेत माफिया पर अंकुश नहीं लगा सका है। जिले में करीब 41 वैध रेत की खदान हैं, लेकिन इतनी ही अवैध रेत खदान हैं, जहां रात के कंकड़ बड़ी मात्रा में रेत का उत्खनन होता है। अवैध रेत उत्खनन रोकने के लिए कई कार्रवाई में सबसे ज्यादा नाव से रेत निकलने के प्रकरण सामने आए। दरअसल बड़ी मात्रा में नाव के जरिए रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, लेकिन अब तक इन नावों को

पांच माह में ये हुई कार्रवाई

जबलपुर जिले में पांच माह के दौरान ही बड़ी संख्या में अवैध रेत उत्खनन से लेकर अवैध परिवहन और संग्रहण के प्रकरण बनाए गए। इन प्रकरणों में कलेक्टर राधेन्द्र सिंह ने करीब 14 करोड़ 60 लाख रुपये का जुर्माना तय किया जा चुका है। वहीं कार्रवाई के दौरान सात नाव जब्त की हैं। इसके साथ ही दो पोक्लेन मशीन, चार जेसीबी, तीन हाइवा, तीन डंपर एवं चार ट्रैक्टर-ट्राली को जब्त किया गया है। खनिज के अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन एवं अवैध भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग के अमले द्वारा संयुक्त रूप से एवं अलग-अलग लगातार कार्रवाई की जा रही है।

बनाने वाले पकड़े गए और न ही इन नाव को नदी में ले जाने वालों पर पूरी तरह से शिकंजा कसा जा सका है।

एनसीआरबी रिपोर्ट में सामने आई सच्चाई

मद्र में भविष्य की चिंता में मौत को गले लगा रहे विद्यार्थी इनमें छात्राओं की संख्या ज्यादा



भोपाल, दोपहर मेट्रो

मध्य प्रदेश में छात्र, सरकारी कर्मचारी, किसान और गृहणियां मानसिक तनाव झेल रहे हैं और इसी के चलते वे खुदकुशी कर रहे हैं। एनसीआरबी (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो) द्वारा जारी 2024 की रिपोर्ट में यह चोका देने वाली जानकारी सामने आई है। करियर के तनाव को लेकर विद्यार्थी सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, इनमें भी छात्राओं को भविष्य को लेकर सबसे ज्यादा चिंता रहती है। रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में खुदकुशी के जो आंकड़े सामने आए हैं, वो यही बता रहे हैं। इस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में देश के उन टॉप तीन राज्यों में शामिल हैं, जहां सबसे ज्यादा लोगों ने खुदकुशी की है। इसमें विद्यार्थियों के साथ महिलाएं, किसान और सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी की संख्या सबसे ज्यादा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में आंकड़े सामने आए हैं उसके अनुसार साल 2024 में हर दिन करीब 42 लोग खुदकुशी की। एमपी में इस एक साल में 15400 से ज्यादा लोगों ने खुदकुशी की थी। एनसीआरबी की रिपोर्ट के

जितने बड़े शहर उतने ही ज्यादा मामले

रिपोर्ट में खुदकुशी के जो आंकड़े सामने आए हैं, उनमें मध्य प्रदेश के बड़े शहरों के नाम देश में सबसे ज्यादा आत्महत्या दर वाले शहरों की लिस्ट में शामिल हैं। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में खुदकुशी की दर 34 प्रतिशत से ऊपर बताई गई है और यह देश में चौथे नंबर पर है। वहीं राजधानी भोपाल में यह दर 28 प्रतिशत के ऊपर है और यह देश में सातवें नंबर पर है।

मुताबिक 2024 में मध्य प्रदेश में 1447 विद्यार्थियों ने खुदकुशी की थी। इसमें प्रदेश देश में तीसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र में 1909 और उत्तर प्रदेश में 1585 विद्यार्थियों ने खुदकुशी की थी। सबसे उदने वाली बात यह है कि इनमें छात्राएं सबसे ज्यादा हैं, करियर की चिंता के तनाव में वो यह कदम उठा रही हैं। आंकड़ों के अनुसार एमपी में 2024 में 731 छात्राओं ने खुदकुशी की थी, जो छात्रों से ज्यादा है।

प्रतियोगी परीक्षाओं से बढ़ रहा तनाव

मध्य प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं में सबसे ज्यादा मानसिक तनाव देखने को मिलता है। ऐसे में वे भविष्य की चिंता को लेकर खुदकुशी जैसा कदम उठा लेते हैं। अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को इस मानसिक तनाव से उबरने में मदद करें और उन्हें काउंसिलिंग सेंटर ले जाएं या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से संपर्क करें।

सार्वजनिक यात्री बसों के किराया निर्धारण के लिए आगामी सप्ताह में होगी बैठक

भोपाल। परिवहन विभाग आगामी सप्ताह में सार्वजनिक बसों के किराया निर्धारण के लिए किराया निर्धारण समिति की बैठक आयोजित करने जा रहा है। इस बैठक में बस किराए से सम्बंधित प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया जाएगा। आगामी बैठक को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए दो बस ऑपरेटर प्रतिनिधियों को बैठक में शामिल किया जायेगा, जिससे सर्वसम्मति से लोक-हितैषी निर्णय लिया जा सके। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 में गठित इस स्थायी समिति में प्रमुख सचिव (परिवहन), आर्थिक सलाहकार वित्त, आयुक्त वाणिज्यिक कर और परिवहन आयुक्त, आयुक्त भोपाल संभाग, प्रबंध संचालक राज्य परिवहन उपक्रम और परिवहन आयुक्त द्वारा नामांकित दो बस ऑपरेटर प्रतिनिधि शामिल हैं। इस दोतरफा संवाद से बस ऑपरेटरों के हित में एक संतुलित व व्यावहारिक निर्णय लिया जाएगा।

मेट्रो एंकर

भोपाल, दोपहर मेट्रो

भोपाल ने निर्यात के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए बीते चार वर्षों में 118 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2021-22 में जहां जिले का कुल निर्यात 1,062.89 करोड़ रुपये था, वहीं वर्ष 2025-26 में यह बढ़कर 2,323.58 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। कृषि एवं खाद्य उत्पादों के साथ इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षेत्र की बढ़ती वैश्विक मांग ने भोपाल को मध्य प्रदेश के प्रमुख निर्यात केंद्रों की श्रेणी में ला खड़ा किया है।

कुल निर्यात 2025-26 में 2,323.58 करोड़ तक पहुंचा कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने इस उपलब्धि को उद्योगों, निर्यातकों और

मद्र में 30 जून से फोन पर सरकारी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बंद;

500 से घटकर 50 से कम कॉल पर सिमट गई सेवा एसएचए ने लिया हेल्पलाइन बंद करने का फैसला



भोपाल, दोपहर मेट्रो

मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों से फोन पर अपॉइंटमेंट लेने की सुविधा जल्द ही समाप्त होने जा रही है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) आगामी 30 जून के बाद अपनी टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 18002332085 आधारित अपॉइंटमेंट सेवा को पूरी तरह बंद करने जा रही है।

इस निर्णय के बाद सरकारी अस्पतालों में फोन कॉल के जरिए डॉक्टरों की उपलब्धता जानना,

अस्पताल सेवाओं की जानकारी प्राप्त करना और ओपीडी अपॉइंटमेंट बुक करने की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक स्रोतों के अनुसार, कोविड महामारी के दौर में शुरू हुई इस हेल्पलाइन सेवा को %बिल क्लिंटन फाउंडेशन% के सहयोग और मदद से संचालित किया जा रहा था। शुक्रआती दिनों में इस सेवा की उपयोगिता बहुत अधिक थी और प्रतिदिन करीब 500 मरीज फोन कॉल के जरिए इस सुविधा का लाभ

डिजिटल ओपीडी पर जोर

प्रशासनिक स्तर पर जहां इसे शत-प्रतिशत डिजिटल ओपीडी की ओर बढ़ता कदम माना जा रहा है, वहीं जमीनी स्तर पर इसके कुछ विपरीत प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं- बुजुर्गों की बढ़ती आफत: प्रदेश की ग्रामीण और बुजुर्ग आबादी अभी पूरी तरह से डिजिटल टूल्स या मोबाइल ऐप का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है। उनके लिए फोन पर बात करके नंबर लगाना सबसे सुगम माध्यम था।

उठा रहे थे। लेकिन वर्तमान में सरकारी अस्पतालों में ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल ऐप और डिजिटल ओपीडी सिस्टम (अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली) लागू होने से इस हेल्पलाइन पर निर्भरता काफी कम हो

टोकन के बाद भी कतारें:

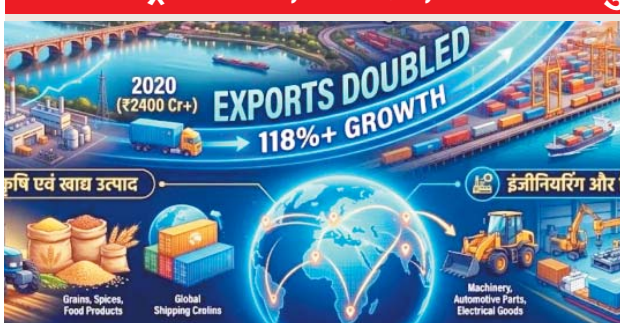
कार्यकर्ताओं ने यह मुद्दा भी उठाया है कि कई बार ऑनलाइन माध्यम से टोकन जनरेट होने के बाद भी मरीजों को वास्तविक पर्चा बनवाने के लिए अस्पतालों में लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, जिससे परेशानी जस की तस भी हुई है। इन जिलों में ही सेवा: कोविड काल के बाद भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास और सीहोर सहित कई जिलों में संचालित हो रही थी यह विशेष व्यवस्था संचालित की जा रही थी।

गई है। अब कॉल की संख्या घटकर प्रतिदिन 50 से भी कम रह गई है। कॉल की घटती संख्या, सेवा संचालन की बढ़ती लागत और बजट में आई कमी को इस हेल्पलाइन को बंद करने की मुख्य वजह माना जा रहा है।

चार वर्ष में दोगुना हो गया भोपाल का निर्यात

अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ईराक सहित कई देशों में जा रहे उत्पाद

ट्रांसफार्मर, टरबाइन, जनरेटर के पुर्जों की मांग



प्रशासनिक संस्थाओं के समन्वित प्रयासों का परिणाम बताया है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिले का कुल निर्यात 1,062.89 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 2,323.58 करोड़ रुपये तक

वहीं, इंजीनियरिंग एवं विनिर्माण क्षेत्र भी निर्यात वृद्धि का मजबूत आधार बनकर उभरा है। भोपाल में निर्मित पावर ट्रांसफार्मर, टरबाइन, जनरेटर के पुर्जे, विद्युत उत्पन्न तथा बेयरिंग हाउसिंग जैसे उत्पादों की वैश्विक बाजारों में लगातार मांग बढ़ रही है।

ताजे केले, बासमती चावल, सोयाबीन मील और अंगूर जैसे उत्पादों ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूत पहचान बनाई है। इन उत्पादों की बढ़ती मांग ने किसानों और कृषि आधारित उद्योगों को भी नए अवसर उपलब्ध कराए हैं।

उद्योगों को वैश्विक मानकों के अनुरूप कर रहे विकसित

कलेक्टर ने बताया कि जिला प्रशासन, एमएसएमई विभाग, एमपीआइडीसी और विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के संयुक्त प्रयासों से स्थानीय उद्योगों को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। नए बाजारों तक पहुंच बढ़ाने और निर्यातकों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में भोपाल देश के अग्रणी निर्यात हब के रूप में अपनी पहचान और अधिक मजबूत करेगा।

युद्ध जब शुरू होते हैं तो उनके पक्षधर अक्सर विजय, सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की बातें करते हैं। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है, युद्ध का असली चेहरा सामने आने लगता है। तब विजेता और पराजित की रेखाएं धुंधली पड़ जाती हैं और सबसे स्पष्ट दिखाई देता है केवल विनाश। मध्य- पूर्व में जारी संघर्ष के सौ दिन पूरे होने के बाद दुनिया आज इसी कठोर सच्चाई का सामना कर रही है। यह टकराव अब केवल दो देशों या दो राजनीतिक ध्रुवों के बीच का मामला नहीं रह गया है। इसकी लपटें वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार, व्यापार मार्गों और करोड़ों आम लोगों

के जीवन तक पहुंच चुकी हैं। समुद्री परिवहन के महत्वपूर्ण रास्तों पर असुरक्षा बढ़ने से अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हुआ है। ऊर्जा आपूर्ति में बाधाएं पैदा हुई हैं और तेल-गैस की कीमतों में उछाल ने दुनिया भर के देशों की आर्थिक योजनाओं को झकझोर दिया है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इतने लंबे संघर्ष के बाद भी कोई निर्णायक परिणाम सामने नहीं आया। सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के बावजूद किसी पक्ष को स्पष्ट बढ़त नहीं मिली है। यही कारण है कि यह युद्ध अब रणनीतिक उपलब्धि से अधिक राजनीतिक जिद और प्रतिष्ठा की

दुनिया की थकान

लड़ाई प्रतीत होने लगा है। दोनों पक्ष शांति की बात भी करते हैं और समानांतर रूप से सैन्य गतिविधियां भी जारी रखते हैं। परिणामस्वरूप युद्धविराम की घोषणाएं भी स्थायी भरोसा पैदा नहीं कर पा रही हैं। इतिहास बताता है कि लंबे युद्ध केवल सीमाओं को नहीं बदलते, वे समाजों की आर्थिक और मानवीय संरचनाओं को भी कमजोर कर देते हैं। लाखों लोगों का विस्थापन, हजारों जानों का नुकसान और बुनियादी ढांचे का विनाश किसी भी संघर्ष की सबसे बड़ी कीमत होती है। लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान वह होता है जो धीरे-धीरे आम नागरिकों

की रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देता है-महंगाई, बेरोजगारी, खाद्य संकट और भविष्य की अनिश्चितता के रूप में। भारत जैसे देशों के लिए भी यह स्थिति चिंता का विषय है। ऊर्जा कीमतों में वृद्धि का असर सीधे परिवहन, कृषि और घरेलू बजट पर पड़ता है। रसाई गैस से लेकर आवश्यक वस्तुओं तक, हर क्षेत्र में बढ़ती लागत का बोझ अंततः आम परिवारों को उठाना पड़ता है। कोई भी युद्ध अंततः बातचीत की मेज पर ही समाप्त होता है। यदि वैश्विक नेतृत्व सचमुच स्थिरता और समृद्धि चाहता है, तो उसे सैन्य प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़कर समाधान की राजनीति अपनानी होगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व के 12 वर्ष

डॉ. मोहन यादव

मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश



प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा नये भारत के निर्माण का स्वर्णिम अध्याय...

भारत के इतिहास में श्री नरेन्द्र मोदी का लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनना देश के लिये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लगातार 3 बार सत्ता में आना श्री मोदी की कार्यप्रणाली, सभी को साथ लेकर चलना और देश को सुरक्षा देने के साथ आर्थिक रूप से मजबूत बनाना ही उनकी विशेषता रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की इन्हीं विशेष खूबियों ने नये भारत के निर्माण का स्वर्णिम अध्याय लिखा है। यशस्वी श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब देश की जनता ने केवल एक सरकार नहीं चुनी थी, बल्कि शासन की एक नई कार्यशैली और राजनीतिक संस्कृति की अपेक्षा भी व्यक्त की थी। बारह वर्ष बाद इस यात्रा को केवल योजनाओं, आंकड़ों और उपलब्धियों के आधार पर नहीं, बल्कि उस व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर समझना अधिक उचित होगा, जिसने शासन की सोच को प्रभावित किया। यदि इन बारह वर्षों को तीन शब्दों में समेटना हो, तो वे शब्द होंगे— सेवा, सुशासन और संकल्प।

हैं। छत्र-छात्राओं को परीक्षा के समय आत्म मजबूत करने के लिये परीक्षा पर चर्चा जैसे विषयों पर उनका संवाद लगातार जारी रहता है। इसी क्रम में उनकी मन की बात कार्यक्रम को पूरा देश बड़े आत्मीय तरीके से आत्मसात करता है। यही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की विशेषता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी की सरकार की कार्यशैली में यह स्पष्ट दिखाई दिया जाता है कि बड़े निर्णयों से बचने के बजाय उन्हें समाधान तक कैसे पहुंचाया जाए? दरअसल, इसे ही निर्णायक नेतृत्व कहते हैं। यह निर्विवाद है कि निर्णय लेने की क्षमता इस शासनकाल की प्रमुख पहचान रही है। इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में मोदी सरकार ने विकसित भारत को राष्ट्रीय संकल्प के रूप में



प्रस्तुत किया। यह संकल्प केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है। इसके भीतर आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गौरव की भावना भी जुड़ी हुई है। पिछले बारह वर्षों में बार-बार यह संदेश दिया गया कि भारत को केवल विकासशील राष्ट्र के रूप में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे विश्व की अग्रणी शक्तियों में स्थान प्राप्त करना चाहिए। यह दृष्टिकोण भारतीय समाज में एक नए आत्मविश्वास का निर्माण करता है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से प्रेरणा लेकर हमने भी विकसित मध्यप्रदेश का सपना देखा। यह बनाते हुए मन भाव-विभोर है कि मोदीजी का हर कदम पर हर निर्णय पर मार्गदर्शन, स्नेह और आशीर्वाद मिला। चाहे वर्षों से लंबित केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध - चंबल लिंक परियोजना हो या पीएम मित्र पार्क, उन्होंने आगे बढ़कर परेशानियों को दूर किया। उनके जैसा नेतृत्व दुर्लभ है। हाल ही में देश के सात राज्यों में पीएम मित्र पार्क बनाने का निर्णय हुआ, तो उस सूची में मध्यप्रदेश को भी रखा गया। यह अति प्रसन्नता का विषय है कि अब तक सिर्फ मध्यप्रदेश में ही पीएम मित्र पार्क का भूमिपूजन हुआ है और यह गौरव का विषय रहा कि धार में पार्क के भूमिपूजन में प्रधानमंत्री जी शामिल हुए। यह सब मध्यप्रदेश से उनके विशेष लगाव का परिणाम ही है।

प्रदेश में साइबर तहसील का सफल क्रियान्वयन हो या भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल, सब प्रधानमंत्रीजी के स्नेह-आशीर्वाद-मार्गदर्शन का ही परिणाम है। आज प्रदेश में नौ एयरपोर्ट हैं, तो इसके पीछे भी उनका ही मार्गदर्शन है। आज हमारा मध्यप्रदेश नक्सल मुक्त है, तो इसके पीछे उनका ही दिशा-निर्देश है। उन्होंने समय-समय पर समझाया, तो

चेताया भी। उन्होंने कहा कि गोली का जवाब गोली से दो पर जो लोग बंदूक-हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौट रहे हैं, उनके लिए बेहतर से बेहतर पुनर्वास की व्यवस्था भी हो। उनकी सलाह-चेतावनी का ही सुफल है कि आज मध्यप्रदेश लाल सलाम को आखिरी सलाम कह चुका है।

प्रधानमंत्रीजी के मार्गदर्शन में ही मध्यप्रदेश में उद्योगों का जाल बिछ रहा है, लाखों करोड़ का निवेश हो रहा है। फरवरी 2025 में भोपाल में आयोजित ग्लोबल इवेस्टर्स सम्मिट में शामिल होना, उनका विशेष स्नेह ही तो दर्शाता है। उन्होंने हमें संवेदना की सीख दी है। उनकी सीख ही थी कि हमने अपने शुरूआती निर्णयों में ही इंदौर के हनुमचंद मिल के कामगारों को उनका बकाया अधिकार दिलवाने में सफलता हासिल की। कामगारों को चेक सॉपने के अक्सर पर आयोजित कार्यक्रम को प्रधानमंत्रीजी ने वचुअली संबोधित भी किया था। मध्यप्रदेश के सभी 55 जिलों में अग्रणी सरकारी कालेजों को प्रधानमंत्री कालेज आफ एक्सिलेंस के रूप में विकसित करना हो या हाइवे का विकास हो, हर मोर्चे पर प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़कर रूचि दिखाई, मार्गदर्शन-मदद और स्नेह देते रहे। मुझे कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि वे कालजयी, त्रिकालदर्शी नेता हैं। हमारे मार्गदर्शक और संरक्षक मोदीजी के कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण विशेषता सांस्कृतिक चेतना का पुनर्स्थापन भी है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने आधुनिकता को अपनाया, लेकिन अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेकर संकोच दिखाई दिया। पिछले बारह वर्षों में भारतीयता, विरासत और सभ्यता पर गर्व करने का भाव अधिक मुखर होकर सामने आया है। यह विचार केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक यात्रा को आधुनिक राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का प्रयास भी है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, काशी का पुनर्विकास हो, या विषय मंचों पर भारतीय परंपराओं और योग का प्रचार-इन सभी के पीछे सांस्कृतिक आत्मविश्वास का वही भाव दिखाई देता है। उनसे प्रेरणा प्राप्तकर मध्यप्रदेश भी अपनी विरासत को संजो रहा है। किसी भी राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी अर्थव्यवस्था या सेना में नहीं होती। उसकी शक्ति उसके आत्मविश्वास में भी होती है। इस दृष्टि से सांस्कृतिक पुनर्जागरण मोदीजी के कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 12 वर्षों को यदि केवल योजनाओं और आंकड़ों से समझने का प्रयास किया जाए, तो तस्वीर अधूरी रह जाएगी। इन 12 वर्षों का वास्तविक महत्व उस सोच में है, जिसने शासन को सेवा से, प्रशासन को सुशासन से और राजनीति को संकल्प से जोड़ने का सफल प्रयास किया है। यह कालखंड भारत के आत्मविश्वास, आकांक्षाओं और राष्ट्रीय चेतना के पुनर्जागरण का कालखंड रहा है। यह नए भारत की आधारशिला है।

-यह लेखक के अपने विचार हैं।

परीक्षाओं के संवेदनशील विषय पर देश - प्रदेश की सरकारों का रुख चिंतनीय

गिरीश्वर मिश्र

महात्मा गाँधी हिंदी विवि के पूर्व कुलपति



राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाओं की छिछलेदर देखते हुए यह सवाल उठाना बेहद जरूरी हो गया है कि सरकार कब इस विषय पर गंभीर होगी और कुछ निर्णायक कदम उठाएगी। ऐसी परीक्षाओं की साख बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। बार-बार नीट जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में गड़बड़ी होना अक्षम्य है। पिछली बार की गड़बड़ी से सबक न लेते हुए एनटीए ने इस बार की परीक्षा की बलि ले ली और लाखों छात्रों को मुश्किल में डाल दिया। पहले की तरह सरकार को और से जांच-पड़ताल की कार्रवाई की सूचना जारी हो चुकी है। संसद की स्थायी समिति ने भी काम शुरू कर दिया है। समिति के सदस्य माननीय सांसद एनटीए से 'पेपर लीक' की परिभाषा पूछने और जानने में लगे हुए हैं।



अखबारी खबर के अनुसार एनटीए का कहना है कि 'गैस पेपर' यानी अनुमानित प्रश्न को 'पेपर लीक' नहीं कहा जा सकता इसलिए जो भी हुआ वह पेपर लीक ही नहीं है। बात कानूनी अर्थ लगाने की है। अब यदि कोई अभ्यर्थी या अध्यापक या फिर कोचिंग संस्थान प्रश्नपत्र का सटीक अनुमान लगा ले तो क्या किया जा सकता है? मेधावी लोग कुछ भी कर सकते हैं। स्थिति हास्यास्पद हो रही है क्योंकि सभी अपने-अपने दायित्व को मुस्तेदी से निभाने की जिम्मेदारी निभाते दिखने की भारी-भरकम कवायद में जुटे हुए हैं। यह अद्भुत दृश्य उपस्थित है : वे यही कह रहे हैं कि जो है या जो हुआ वह स्वाभाविक है यानी वही हो ही सकता था ! परीक्षा की नई तारीख मुकर्रर कर दी गई है। भगवान करे वह परीक्षा बिना किसी विवाद के हो जाय और युवा वर्ग को अपने जीवन के पथ पर चलने का एक अवसर मिले।

गौरतलब है कि अन्य परीक्षाओं में भी धांधली की अनेक घटनाएँ सामने आती रही हैं और अनुचित साधनों का इस्तेमाल कर फायदा उठाने के मसले भी पकड़ में आते रहे हैं। अक्सर इन मामलों में समय पर कार्रवाई नहीं होती या फिर कार्रवाई ही नहीं होती। जो भी हो अक्सर अपराधी दण्डित नहीं हो पाते। दूसरी तरफ बहुत से निरपराधी छात्रों का एकगुनाह होते हुए भी नाहक ही अच्छ-खासा नुकसान उठाना पड़ता है। व्यवस्था

अपनी जगह चलती रहती है। सच कहा जाय तो यह समस्या सुविधा और शार्टकट के सहारे सस्ते में लाभ कमाने की व्यापक होती जा रही संस्कृति का ही हिस्सा है। पैसा कमाने की चाह जाने कितने तरह के अनैतिक, भ्रष्ट और अपराधिक किस्म के शलत कार्यों को प्रोत्साहन देती है।

कुछ दिनों पहले नीट मामले में यह खबर भी आई थी कि कुछ अध्यापक जिन्हें एनटीए ने योग्य माना और परीक्षा के गोपनीय कार्य में लगाया उन्होंने फ़ौरी अर्थ लाभ पाने की आशा से परीक्षा के प्रश्न पत्र के साथ छेड़खानी की और पेपर लीक हो गया था। उन अध्यापकों को गिरफ्तार भी किया गया था। इस समस्या का एक नया आयाम डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग से भी जुड़ गया है।

इंटरनेट की सुविधाएँ, सर्च इंजिन और सर्वर आदि की समस्या के कारण परीक्षा से जुड़े कामों में बाधा उत्पन्न होती है। सीबीएसई के ताजा मामले में कुछ यही हुआ है जिसे अब आईआईटी की तकनीकी सहायता से दूर

किया जा रहा है। यह विडंबना ही कहीं जाएगी कि शिक्षण और परीक्षण के बीच अब दो फाँक हो चुकी है। पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला और पढ़ाई की पड़ताल करने वाला और जीविका देने वाला धीरे-धीरे एक-दूसरे से दूर होते गए हैं। उनका आपस में एक-दूसरे पर कोई भरोसा नहीं है। शिक्षा पूरी करने के बाद नौकरी पाने के लिए या व्यवसाय की दुनिया में कदम रखने के वक्त परीक्षा के लिए लोक सेवा आयोग जैसी संस्थाएँ देश और प्रदेश के स्तर पर बनाई गई थीं और बहुत हद तक उनकी साख अब भी अक्षुण्ण बनी हुई है।

परीक्षा बहुत से छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो रही है। उसके लिए भी उच्चतम न्यायालय ने सरकार को फटकार लगाई है और सरकार की ओर से कमेटी भी बन गई है। कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। काश इन जांचों, समितियों और उनकी संस्तुतियों को लेकर कुछ ठोस कदम भी उठाए जाते जरूरी है कि उनके सुझावों को ठंडे बस्ते में न डालकर उन पर अमल करने की दिशा में हम आगे बढ़ें। देश के भविष्य के लिए शिक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पारिस्थितिकी (इकोलॉजी) पर विचार करना जरूरी है। छात्रों के स्वास्थ्य और हित को सुरक्षित रखने का उद्यम सभी को एक साझा दायित्व है।

-यह लेखक के अपने विचार हैं।

हेल्थ टिप्स

मोरिंगा का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है। मोरिंगा की पत्तियों में कई तरह के विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसे सहजन के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर अर्चना बत्रा डाइटिशियन एंड सर्टिफाइड डायबिटिक एजुकेशन बताती हैं कि मोरिंगा की पत्तियों में क्वेरसेटिन, क्लोरोजेनिक एसिड और बीटा-कैरोटीन जैसे कंपाउंड होते हैं, जो शरीर में ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही मोरिंगा इम्यूनिटी को मजबूत बनाने, आयरन लेवल को बढ़ाने, थकान को कम करने, ब्लड शुगर को मैनेज करने और हार्ट, स्किन व बालों के



लिए भी फायदेमंद माना जाता है। डाइटिशियन अर्चना के अनुसार मोरिंगा की पत्तियों को बहुत पोषिक माना जाता है क्योंकि उनमें कई तरह के विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट और प्लांट प्रोटीन होते हैं। मोरिंगा की फ्रेश पत्तियां विटामिन सी, विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फोलेट से भरपूर होती हैं। साथ ही, इसमें आवश्यक अमीनो एसिड भी होते हैं, जो खासकर शाकाहारियों के लिए इसे एक कीमती प्लांट-बेस्ड प्रोटीन स्रोत बनाते हैं। इम्यूनिटी को बेहतर करना: मोरिंगा की पत्तियों के फायदे में सबसे

पहले आप मजबूत इम्यूनिटी पावर को रख सकते हैं। मोरिंगा में इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए आवश्यक विटामिन ए, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। यह शरीर के नेचुरल डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और किसी भी तरह के डैमेज से सेल्स को बचाने में मदद करते हैं। मौसम में होने वाले बदलाव व इंप्रूवमेंट के दौरान आप मोरिंगा का सूप पी सकते हैं। इससे एनर्जी लेवल बेहतर होता है और आपकी रिकवरी तेजी से होती है। इसकी पत्तियों में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो आपकी गट हेल्थ को बेहतर करती है। यह आपके बाउल मूवमेंट में भी सुधार करती है। इससे हेल्दी गट बैक्टीरिया को सपोर्ट मिलता है और खराब खाने की वजह से होने वाली परेशानी दूर होती है। गट हेल्थ बेहतर होने से

व्यक्ति के मोटापे और वजन में भी कंट्रोल होता है। मोरिंगा की फ्रेश पत्तियों को आप दाल, सूप, करी, ऑमलेट और पराठों में मिलाकर ले सकते हैं। इसके अलावा, मोरिंगा पाउडर को स्मूदी, छाछ, हर्बल टी या सूप में मिलाया जा सकता है, या फिर सलाद के ऊपर छिड़का जा सकता है। चूँकि मोरिंगा का स्वाद थोड़ा मिठ्टी जैसा होता है, इसलिए शुरूआत में इसे कम मात्रा में लेना ही सबसे अच्छा रहता है। इसके पोषक तत्व आपको कमजोरी, थकान, खून की कमी, हार्ट से संबंधित बीमारियों और डायबिटीज आदि के जोखिम से बचाने में मदद करते हैं। यदि आपको पहले से किसी तरह की बीमारी या एलर्जी है तो ऐसे में डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसे डाइट में शामिल करें।

सुविचार

हमें थोड़ा बहुत बर्दाशत करना सीखना चाहिए, क्योंकि हममें भी बहुत सी कमियाँ हैं जो दूसरे लोग बर्दाशत कर लेते हैं। -अज्ञात

निशाना

जिंदगी ऐसे गुजारी जाये..!



रामकिशोर नाविक

जिंदगी ऐसे गुजारी जाये साथ न ले के उधारी जाये शेर, उतरें यूँ आपके दिल में जैसे मंदिर में पुजारी जाये अज्ञ है मेरी आप हों कह दें बात खाली ना हमारी जाये देखते रहें और मन ना भरे ऐसी तस्वीर उतारी जाये किसी भी तौर याद कर लेना हमसे वापत ना सुधारी जाये

टेक्नो अपडेट

अब कारोबार में भी मदद करेगा वॉट्सऐप मैसेंजर और इंस्टाग्राम का नया AI फीचर

मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग अब चाहते हैं कि AI सिर्फ लोगों की मदद ही न करे, बल्कि छोटे और बड़े कारोबार भी सँभाले। इसी दिशा में कंपनी ने पिछले दिनों एक नया AI एजेंट लॉन्च किया, जो वट्सऐप, इंस्टाग्राम और मैसेंजर पर कारोबारियों की ओर से ग्राहकों से बात कर सकेगा, सवाल्लों के जवाब देगा, अपॉइंटमेंट बुक करेगा और

यहां तक कि बिक्री भी पूरी कर सकेगा। अगर सरल तरीके से कहें तो यह AI एजेंट किसी कंपनी का डिजिटल कर्मचारी होगा, जो 24 घंटे काम कर सकेगा। मन लॉजिए, आपकी ऑनलाइन बेकरी है। अभी ग्राहक केक का ऑर्डर देने के लिए मैसेज करते हैं और आपको या आपके स्टॉफ को जवाब देना पड़ता है। नया AI एजेंट ग्राहक से खुद बात करेगा, केक के विकल्प बताएगा, कीमत बताएगा, ऑर्डर लेगा और डिलीवरी की जानकारी भी दे देगा। यानी कई काम बिना इंसानी दखल के पूरे हो जाएंगे।

अगर अपने कारोबार के लिए यह AI एजेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको Meta Business Suite या WhatsApp Business अकाउंट की जरूरत होगी। मेटा धीरे-धीरे इस फीचर को कारोबारियों के लिए उपलब्ध करा रही है। फीचर मिलने पर बिजनेस प्रोफाइल अपने प्रोडक्ट, कीमतें, स्टॉक, काम के घंटे और अवसर



पूछे जाने वाले सवाल AI को सिखा सकेगा। इसके बाद ग्राहक जब वट्सऐप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करेगा, तो AI खुद जवाब देगा।

10 लाख कारोबारी कर रहे इस्तेमाल: कंपनी ने बताया कि यह AI एजेंट पहले कुछ देशों में सीमित स्तर पर टेस्ट किया जा चुका है और करीब 10 लाख व्यवसाय पहले से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल यह सेवा मुफ्त होगी, लेकिन अगले कुछ महीनों में इसे सर्वरिक्लेशन मॉडल पर लाया जाएगा। यानी कारोबारियों को इसके लिए शुल्क देना होगा। छोटे और बड़े व्यवसायों के लिए अलग-अलग प्लान हो सकते हैं। मेटा बड़ी कंपनियों के लिए भी एक अलग AI प्लेटफॉर्म ला रही है।

मेटा ने Meta Business Agent Platform नाम का एक नया प्लेटफॉर्म भी पेश किया है। इसकी मदद से बड़ी कंपनियां अपनी जरूरतों के अनुसार कस्टम AI एजेंट तैयार कर सकेंगी और उन्हें बड़े स्तर पर तैयार कर पाएंगी। यह प्लेटफॉर्म Shopify और Zendesk जैसे सैकड़ों बिजनेस टूल के साथ इंटीग्रेशन सपोर्ट करेगा। इससे एजेंट सीधे कंपनी के सिस्टम तक पहुंचकर विभिन्न कार्यों को अंजाम दे सकेंगी। अभी कारोबारी Meta Business Agent का इस्तेमाल बिना किसी शुल्क के कर सकते हैं।

समुद्र की गहराइयों में रचा गया इतिहास, 52 मीटर नीचे पानी के भीतर बना वर्ल्ड रिकॉर्ड

समुद्र की गहराइयों हमेशा से इंसानों के लिए रहस्य और रोमांच का केंद्र रही हैं। सतह से नीचे जाते ही एक ऐसी दुनिया शुरू होती है, जहाँ रोशनी कम हो जाती है और हर कदम पर नई चुनौतियां इंतजार करती हैं। हाल ही में इसी रहस्यमयी दुनिया के बीच एक ऐसा कारनामा किया गया, जिसने दुनियाभर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। समुद्र की 52.1 मीटर गहराई में एक विशेष अंडरवॉटर फोटोशूट कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है।

यह रिकॉर्ड भारतीय वॉच ब्रांड टाइटन के नाम दर्ज हुआ है। कंपनी ने अपनी नई प्रोफेशनल डाइविंग वॉच सीरीज के लिए समुद्र के भीतर एक अनोखा प्रोडक्ट फोटोशूट आयोजित किया, जिसे बाद में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिली। इस उपलब्धि को समुद्र की गहराइयों में किए गए सबसे गहरे प्रोडक्ट फोटोशूट्स में से एक माना जा रहा है। इस साहसिक अभियान के लिए थाईलैंड के प्रसिद्ध राचा नोई द्वीप को चुना गया है। यह स्थान अपने साफ पानी और बेहतरीन डाइविंग स्पॉट्स के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। मिशन को अंजाम देने के लिए पांच प्रशिक्षित टेक्निकल डाइवर्स की टीम बनाई गई, जिन्होंने समुद्र की कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए इस चुनौती को सफल बनाया।

अभियान के दौरान गोताखोरों ने पानी में उतरने के कुछ ही मिनटों के भीतर 50 मीटर से अधिक की गहराई हासिल कर ली। टीम आखिरकार 52.1 मीटर नीचे तक पहुंची, जहां पानी का दबाव सामान्य परिस्थितियों की तुलना में कई गुना अधिक होता है। ऐसी परिस्थितियों में काम करना किसी भी डाइवर के लिए आसान नहीं माना जाता। गहराई तक पहुंचने के बाद टीम के पास



फोटोशूट पूरा करने के लिए सीमित समय था। लगभग 20 मिनट के भीतर उन्होंने विशेष कैमरों और तकनीकी उपकरणों की मदद से पूरी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया। सबसे खास बात यह रही कि यह फोटोशूट किसी स्टूडियो या कृत्रिम वातावरण में नहीं, बल्कि समुद्र की वास्तविक परिस्थितियों में किया गया। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार, यह उपलब्धि केवल एक मार्केटिंग अभियान नहीं बल्कि भारतीय डिजाइन, इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन भी है। इस प्रोजेक्ट को जीरो ऑवर नाम दिया गया, जो उस निर्णायक क्षण का प्रतीक है जब सफलता और असफलता के बीच केवल तैयारी और आत्मविश्वास का अंतर होता है।

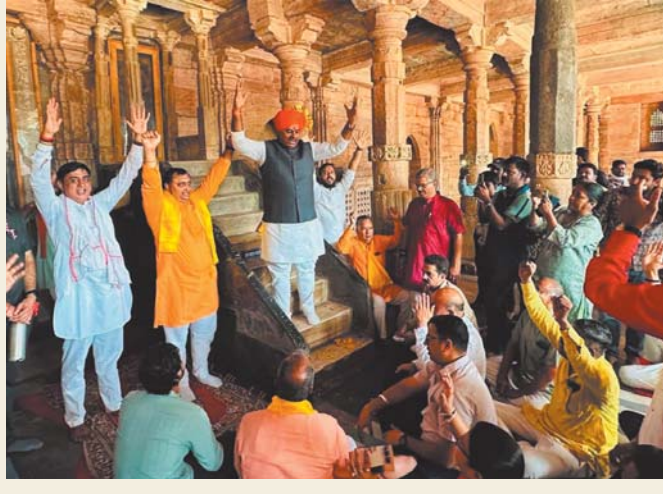
भोजशाला में विधायक शर्मा ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और महाआरती में हुए शामिल

मुस्लिम समाज सत्य स्वीकार कर हिंदुओं को सौंपें भोजशाला

धार। दोपहर मेट्रो

पुरातत्व विभाग के अधीन भोजशाला में इन दिनों श्रद्धालुओं का ताता लगा हुआ है। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पूजन और दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में गत दिवस भोपाल की विधानसभा से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा धार पहुंचे। उन्होंने भोज उत्सव समिति द्वारा आयोजित साप्ताहिक सत्याग्रह में भाग लिया और सुंदरकांड का पाठ किया। विधायक शर्मा ने भोजशाला में मौजूद वाग्देवी (सरस्वती) के चित्र की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और महाआरती में शामिल हुए। इस दौरान भोज उत्सव समिति के पदाधिकारियों ने उन्हें भोजशाला के स्तंभों पर उकेरी गई प्राचीन आकृतियों और यहाँ के गौरवशाली इतिहास की विस्तृत जानकारी दी। हिंदू समाज को संबोधित करते हुए विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा भोजशाला मां सरस्वती का भव्य और दिव्य पावन मंदिर है। अलाउद्दीन खिलजी के दौर से लेकर अब तक कई आक्रांताओं और लोगों ने इस मंदिर को खंडित करने

का षड्यंत्र रचा। लेकिन मैं धार के हिंदू समाज को हृदय से बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस संघर्ष को 700 साल तक जिंदा रखा। उन्होंने आगे कहा कि यह लड़ाई सड़कों से लेकर न्यायपालिका तक लड़ी गई और अखिरकार अदालत ने भी यहाँ के ऐतिहासिक तथ्यों और सत्य को स्वीकार करते हुए न्यायसंगत निर्णय दिया है। मीडिया से चर्चा के दौरान विधायक रामेश्वर शर्मा ने मुस्लिम समाज से एक बड़ी अपील की। उन्होंने कहा, मैं मुस्लिम भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि वे थोड़े बड़े दिल से तथ्यों और सत्य को स्वीकार करें। यह राजा भोज द्वारा निर्मित मां सरस्वती का पवित्र मंदिर है। वे सहर्ष इस भोजशाला को हिंदुओं को सौंपकर गले मिलें। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, अगर ऐसा नहीं हुआ, तो धार के हिंदुओं के इस संघर्ष से देश का हर हिंदू प्रेरणा लेगा। फिर इतिहास में जहाँ-जहाँ पूर्वजों ने गड़बड़ियाँ की हैं, उन सभी स्थानों पर उसके परिणाम दिखाई देंगे।



बनेगा भव्य सरस्वती लोक

भोजशाला के भविष्य और विकास योजनाओं पर बात करते हुए विधायक शर्मा ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संकल्प को दोहराया। कहा कि पुरातत्व विभाग के नियमों और दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, जहाँ-जहाँ निर्माण की अनुमति होगी, वहाँ भव्य विकास कार्य किए जाएंगे। इसके लिए स्थानीय भोज उत्सव समिति और विशेषज्ञों से भी सलाह ली जाएगी। विधायक के अनुसार माँ वाग्देवी की जो मूल प्रतिमा इस समय इंग्लैंड की धरती पर (ब्रिटिश म्यूजियम में) है, उसे आज नहीं तो कल केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से भारत की भूमि पर वापस लाया जाएगा और पूरे सम्मान के साथ धार के इसी पवित्र मंदिर में स्थापित किया जाएगा।

न्यूज विंडो

कोडल तिगड़ा में सड़क पर गिरा पेड़, 12 घंटे बाधित रहा आवागमन



तेंदूखेड़ा। नगर से लगभग 15 किलोमीटर दूर तेंदूखेड़ा तारादेही मुख्य मार्ग पर कोडल तिगड़ा के समीप सोमवार रात्रि करीब 11 बजे एक विशाल पेड़ तेज हवा के कारण सड़क पर गिर गया। पेड़ के मुख्य मार्ग पर गिर जाने से रात से ही आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। मंगलवार सुबह तक मार्ग से पेड़ नहीं हटाए जाने के कारण दोनों ओर बसें, ट्रक एवं अन्य छोटे-बड़े वाहन जाम में फंसे रहे, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम में फंसी बसों में कुछ ऐसे यात्री भी सवार थे जो उपचार के लिए जबलपुर एवं दमोह जा रहे थे। घंटों तक मार्ग अवरुद्ध रहने के कारण वे समय पर चिकित्सकों तक नहीं पहुंच सके। यात्रियों ने इस स्थिति के लिए लोक निर्माण विभाग की उदासीनता को जिम्मेदार ठहराया और विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। सामाजिक कार्यकर्ता राहुल चौकसे ने बताया कि सुबह होते ही उन्होंने तेंदूखेड़ा पहुंचकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को घटना की जानकारी देने का प्रयास किया, लेकिन विभाग का कोई भी अधिकारी मुख्यालय पर उपस्थित नहीं मिला।

कलेक्टर के निर्देश पर तेंदूखेड़ा के मेडिकल स्टोर्स का सघन निरीक्षण



तेंदूखेड़ा। जिला कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के निर्देशानुसार नगर एवं आसपास संचालित मेडिकल स्टोर्स का ड्रग इंस्पेक्टर महिमा जैन द्वारा सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम सी.जी. गोस्वामी एवं तहसीलदार विवेक व्यास भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान दवा दुकानों में उपलब्ध सुविधाओं, साफ-सफाई, दवाओं के भंडारण एवं औषधि विक्रय संबंधी नियमों के पालन की विस्तृत जांच की गई। ड्रग इंस्पेक्टर महिमा जैन ने मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देशित किया कि दवाओं का रखरखाव निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाए तथा ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित दवाएं उपलब्ध कराई जाएं। निरीक्षण के दौरान एकसपायरी दवाओं की उपलब्धता, उनके पृथक भंडारण एवं नियमानुसार निस्तारण की प्रक्रिया की भी जांच की गई। जिन दुकानों में रिकॉर्ड संभारण एवं भंडारण व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पाई गई, उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान यह भी देखा गया कि मेडिकल स्टोर्स का संचालन अधिकृत एवं पंजीकृत फार्मासिस्ट द्वारा किया जा रहा है अथवा नहीं। संबंधित फार्मासिस्ट की उपस्थिति, योग्यता प्रमाण-पत्र तथा लाइसेंस दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। साथ ही सभी मेडिकल स्टोर्स के वैध लाइसेंस एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों की जांच कर नियमानुसार अद्यतन रखने के निर्देश दिए गए।

ईको वलव किसलय द्वारा नवीन निर्माणाधीन सांदीपनि विद्यालय में किया गया पौधरोपण



नरसिंहपुर। पर्यावरण संरक्षण एवं हरित परिसर की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिनांक 8 जून 2026 को नवीन निर्माणाधीन सांदीपनि विद्यालय नरसिंहपुर के प्रांगण में ईको क्लब किसलय द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में 10 पौधों का रोपण किया गया। विद्यालय प्राचार्य प्रभात मिश्रा ने बताया कि रोपित पौधों में प्रमुख रूप से आंवला, नीम, सहजन, अशोक एवं जामुन जैसे फलदार एवं उपयोगी पौधे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि विद्यालय परिवार द्वारा नवीन निर्माणाधीन भवन परिसर को हरा-भरा बनाने के उद्देश्य से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विगत एक वर्ष में विद्यालय परिवार एवं ईको क्लब किसलय के सहयोग से परिसर में लगभग 80 पौधों का रोपण किया जा चुका है। विद्यालय में विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण, वृक्षों के महत्व एवं प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का संदेश भी दिया जा रहा है।

शिकायतों के बाद भी संबंधित अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान

नगर परिषद का कचरा उड़कर पहुंच रहा मिश्रित प्लांटेशन में, आग का बना खतरा

तेंदूखेड़ा। दोपहर मेट्रो

नगर से लगे खकरिया-इमलीडोल मार्ग पर बने मिश्रित प्लांटेशन में इस समय गंदगी एवं कचरे का आलम बना हुआ है। करीब 7 वर्ष पहले बनाए गए मुख्य मार्ग पर बने मिश्रित प्लांटेशन में लगाए गए पौधों के आसपास गंदगी ही नजर आ रही है। इन पेड़ पौधों के पास कचरा एवं गंदगी नगर परिषद की मेहरबानी से पहुंच रही है, पर सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस ओर वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिससे आग की एक चिंगारी इस प्लांटेशन को बर्बाद कर सकती है। मिश्रित प्लांटेशन में गंदगी पहुंचने का प्रमुख कारण नगर परिषद है, इसमें सिर्फ प्लांटेशन से कुछ ही दूरी पर नगर परिषद का सारा कचरा फेंका जाता है। गर्मी एवं हवा के कारण यह कचरा उड़कर प्लांटेशन में पहुंच रहा है

गंदगी को नगर परिषद के फेंके जा रहे कचरे का कारण माना जा रहा है। नगर परिषद जहां अपना कचरा फेंकता है, उसी से लगा वन विभाग का मिश्रित प्लांटेशन है। गर्मी में चल रही हवाओं के कारण यह कचरा प्लांटेशन में पहुंच गया है। जिसके कारण प्लांटेशन में जहां देखो, वहां कचरा एवं पत्तियां ही नजर आ रही है। जिसके कारण किसी दिन एक छोटी सी चिंगारी एक बहुत बड़ा रूप लेकर इस प्लांटेशन में लगे पौधों को



नुकसान पहुंचा सकती हैं। वन विभाग और नगर परिषद का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। कुल मिलाकर मिश्रित प्लांटेशन की देखरेख में लापरवाही की जा रही है। यह प्लांटेशन वर्ष 2019-20 में बनाया गया है। यह प्लांटेशन के रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो अब मुसीबत का कारण बन रहा है। वन प्लांटेशन में

लगे हैं, जो आकार में भी काफी बड़े हो गए हैं, लेकिन नगर परिषद से पहुंचे कचरे से यह प्लांटेशन बड़ी मात्रा में गंदगी फैल गई है। जबकि वन विभाग समय-समय पर पर्यावरण एवं पौधों की सुरक्षा के लिए शपथ लेते हैं पर प्लांटेशन के रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो अब मुसीबत का कारण बन रहा है। वन प्लांटेशन में

नगर परिषद के ट्रेविंग ग्राउंड से उड़कर पहुंच रही पत्तियों से पेड़ों को काफी नुकसान पहुंचा सकता है जिससे पेड़ों को पर्याप्त धूप और पानी नहीं मिल पाता मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है जिसके कारण जड़ों का विकास रुक जाता है जरूरी पोषक तत्वों की कमी से पेड़ पौधों की ग्रोथ रुक जाती है।

शहडोल में विकास की नई ऊंचाइयां, अवैध कोयला उद्योग ने बनाया नया रिकॉर्ड

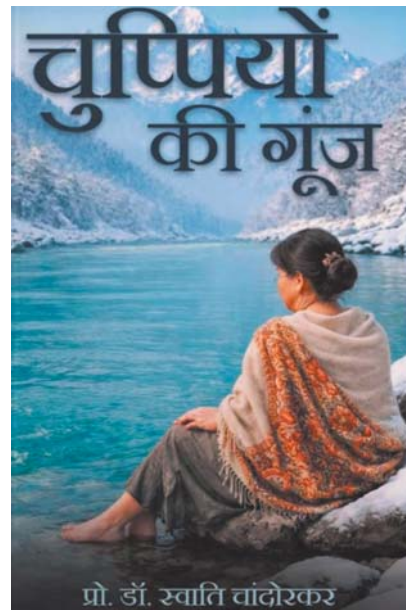
शहडोल। दोपहर मेट्रो

जिले में विकास की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि आंकड़े भी पीछे छूट गए हैं। सूत्रों के अनुसार, जहां पहले लगभग 127 अवैध कोयला गड्डों के संचालन की चर्चा थी, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 140 बताई जा रही है। इस उपलब्धि पर क्षेत्र के अनाम उद्योगपतियों (उर्फ माफिया) ने खुशी जताते हुए इसे आत्मनिर्भरता की मिसाल बताया। इस ऐतिहासिक प्रगति पर जिला प्रशासन को हार्दिक बधाई दी जा रही है, क्योंकि यदि कार्रवाई होती रहती तो शायद यह विकास दर संभव नहीं हो पाती। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस गति से गड्डों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए जल्द ही शहडोल को कोयला स्टार्टअप हब घोषित किया जा सकता है। उधर, माफिया वर्ग ने प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, हमें ऐसा सहयोग और प्रोत्साहन नहीं मिला। यदि यही समर्थन मिलता रहा तो अगले वर्ष 140 से 200 का लक्ष्य भी हासिल कर लेंगे।

लघु उपन्यास चुप्पियों की गूँज, भारतीय समाज में स्त्री का जीवन चुनौतियों से है भरा

नरसिंहपुर। दोपहर मेट्रो

नरसिंहपुर की प्रसिद्ध शिक्षाविद और साहित्यकार डॉ. स्वाति के द्वारा लिखित लघु उपन्यास चुप्पियों की गूँज दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्व में आपकी पुस्तक मेरी नर्मदा परिक्रमा जो की स्वयं की नर्मदा परिक्रमा के अनुभव पर आधारित है बेस्ट सेलर बुक में नामांकित हो चुकी है। आपका पहला उपन्यास वैदेही विद्रोह उन्मुक्त शैली में नारी विमर्श के पटल पर एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में उभरा और इस उपन्यास को राष्ट्रीय स्तर पर चैलेंजिंग पेन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। नरसिंहपुर के पीएम कॉलेज ऑफ एक्सिलेंस स्वामी विवेकानन्द शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की हिंदी विभाग की अध्यक्ष डॉ. नमिता साहू ने लघु उपन्यास चुप्पियों की गूँज पर अपना समीक्षा लेख प्रस्तुत किया। डॉ. नमिता साहू ने कहा की हिंदी साहित्य में सर्वाधिक रोचक और पढ़े जाने वाली विधा में उपन्यास परंपरा रही है। बदलते समय के दौर में लघु उपन्यास लिखने की परंपरा चल पड़ी और सफल भी हुई। प्रभावान्वित की दृष्टि से लघु उपन्यास पाठकों पर अधिक छाप छोड़ने में सफल रहे हैं। जिनका नवीनतम लघु उपन्यास चुप्पियों की गूँज... साहित्य पटल पर उल्लेखनीय है। लेखिका के साहित्य का प्रयोजन स्त्री जीवन के संघर्ष को गहराई से व्यक्त करना है। कथानक



में स्मिता के रूप में स्त्री जीवन की बिड़बना यह है कि विवाह पूर्व पिता का घर, विवाह पश्चात पति का घर, उसमें भी सास और नन्दन का प्रभुत्व है। पिता की मृत्यु होते ही भाई ने भी सदैव के लिए संबंध विच्छेद कर लिया।

उमरिया में नियमों को ताक पर रख दौड़ रही हैं बसें

उमरिया। दोपहर मेट्रो

जिले में संचालित हो रही कुछ निजी यात्री बसों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कटनी से उमरिया और मानपुर मार्ग पर कई बसें बिना वैध फिटनेस प्रमाणपत्र और बिना सक्रिय (व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस) के संचालित हो रही हैं। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि यदि वाहनों के आवश्यक दस्तावेज पूर्ण नहीं हैं तो उन्हें परमिट किस आधार पर जारी किया गया और वे सड़कों पर कैसे दौड़ रही हैं। परिवहन नियमों के अनुसार वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र अनिवार्य होता है, जबकि कई राज्यों में VLTID और पैनेक बटन को भी परमिट व फिटनेस से जोड़ा गया है। बिना फिटनेस के किसी भी परिवहन वाहन का संचालन नियमों के विपरीत माना जाता है। जानकारों का कहना है कि यदि किसी बस का फिटनेस प्रमाणपत्र समाप्त हो चुका है या VLTID सक्रिय नहीं है, तो उसके परमिट और संचालन की वैधता की जांच आवश्यक हो जाती है। वहीं मध्यप्रदेश में बिना वैध परमिट बस संचालन पर सख्त दंडात्मक प्रावधान भी लागू हैं।

मेट्रो एंकर

ग्राम पंचायत मगरपुंछ में बड़ी चोरी, पुलिस जुटी पड़ताल में

लाखों का सामान ले उड़े चोर, रिकॉर्ड जलाकर किए सबूत मिटाने के प्रयास

औबेदुल्लागंज। दोपहर मेट्रो

औबेदुल्लागंज विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मगरपुंछ में अज्ञात चोरों ने पंचायत भवन को निशाना बनाते हुए बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। चोर पंचायत भवन से लाखों रुपये मूल्य का सामान चोरी कर ले गए। हैरानी की बात यह है कि बदमाश पंचायत में लगे सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी अपने साथ ले गए, जिससे उनकी पहचान से जुड़े साक्ष्य मिटाए जा सके।

जानकारी के अनुसार अज्ञात चोर देर रात पंचायत भवन में घुसे और कार्यालय में रखा इलेक्ट्रॉनिक एवं अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। चोरी की वारदात के बाद बदमाशों ने पंचायत के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी नहीं बखलाया। चोरों ने वर्ष 1994 से लेकर वर्तमान तक के पंचायत संबंधी महत्वपूर्ण अभिलेखों एवं रिकॉर्ड में आग लगा दी, जिससे बड़ी मात्रा में दस्तावेज नष्ट हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों में हड़कंध मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच



शुरू कर दी, पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। वहीं पंचायत के महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जलने से

प्रशासनिक कार्यों पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं से जांच की जा

रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा।

मगरपुंछ ग्राम पंचायत सरपंच रामकिशोर गौर ने बताया कि आज सुबह-सुबह मेरे को फोन पहुंचा, तो मैं घर से आया, पंचायत भवन की लाइट काट गए और वो सामान ले गए, कैमरे ले गए, कम्प्यूटर ले गए, और आगजनी कर गए, सब कागजात पूरे जला दिए। पंचायत का रिकॉर्ड, पंचायत का रिकॉर्ड पूरा जला दिए। आज सुबह-सुबह तीन-चार बजे के करीब की घटना है। मगरपुंछ ग्राम पंचायत सचिव देवीदास ओढ़ ने बताया कि ग्राम पंचायत मुख्यालय के मुख्य गेट के ताले तोड़े गए, उसके बाद अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ग्राम पंचायत भवन से कैमरे, रिसेवर एवं अन्य सामग्री चोरी की गई। इसके बाद दोनों गोदरेज के ताले तोड़े, ताले तोड़ने के पश्चात आग जला दी उनके ऊपर और पूरा रिकॉर्ड 1994 से लेकर अभी तक का पूरा जलाया गया। लगभग 1 लाख रुपये का नुकसान हुआ है संपत्ति का। पूरी ग्राम पंचायत इससे प्रभावित होगी, आने वाले समय में कोई भी जानकारी ग्राम पंचायत से देने में असमर्थ रहेंगे।

दंगे की आग में जल रहा आयरलैंड...



चाकूबाजी की घटना के बाद भड़के लोग, घरों और गाड़ियों में लगाई आग

डबलिन, एजेंसी। उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में एक व्यक्ति पर हुए क्रूर चाकू हमले के बाद तनाव काफी बढ़ गया है। घटना के विरोध में सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को अपनी बख्तरबंद यूनिट को तैनात करना पड़ा है।

अधिकारियों ने इस हमले को बेहद क्रूर बताया है, जिसमें पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर सहित कई राजनीतिक नेताओं ने इस हिंसा की कड़ी निंदा की है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

सूडानी नागरिक गिरफ्तार: उत्तरी आयरलैंड की पुलिस ने मंगलवार को चाकू हमले के सिलसिले में एक 30 वर्षीय सूडानी नागरिक को गिरफ्तार किया। सोमवार देर रात उत्तरी बेलफास्ट में हुए इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया था। वीडियो सामने आने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस घटना को भयावह करार दिया। हालांकि, पुलिस फिलहाल इस घटना को आतंकवाद से जोड़कर नहीं देख रही है। उत्तरी आयरलैंड के सहायक मुख्य कांस्टेबल रयान हेंडरसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे गंभीर घटना घोषित किया। उन्होंने कहा, 'मैं समझता हूँ कि कल रात हत्या के इस प्रयास से लोगों के मन में डर और गुस्से की भावनाएं पैदा होंगी।'

न्यूज विडो

उत्तराखंड एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई कार में मिले अवैध हथियार, हड़कंप काशीपुर।

स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए काशीपुर के बड़े गुरुद्वारे के पास पार्किंग में खड़ी कार से अवैध हथियार और फर्जी लाइसेंस पकड़े हैं। एसटीएफ ने मुखबिर की सूचना पर काली मंदिर के पास यह कार्रवाई की है। हथियारों को कब्जे में लेकर जा शुरू कर दी है। एसटीएफ ने बाहरी राज्यों से स्थानांतरित होकर आए शस्त्र लाइसेंसों की पिछले दो माह से जांच शुरू की है। पिछले दिनों काशीपुर में 10 फर्जी लाइसेंस मिलने के बाद दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। एसटीएफ को सूचना मिली कि वाहन में अवैध हथियार और फर्जी लाइसेंस रखे गए हैं। एसटीएफ की टीम ने कार की तलाशी ली। कार से कुछ असलहे और कई सदिध लाइसेंस बरामद किए हैं। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में हड़कंप मच गया और मीके पर लोगों की भीड़ जुट गई। रामद दस्तावेजों और हथियारों की जांच की जा रही है। रात 11 बजे तक कार्रवाई जारी थी। टीम में निरीक्षक एनपी सिंह, अरुण कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। एसटीएफ ने बरामद हथियारों के बारे में अभी जानकारी नहीं दी है।

दयारा बुग्याल ट्रैक से युवती गायब 100 जवान लगे सर्व ऑपरेशन में



उत्तरकाशी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दयारा बुग्याल ट्रैक से एक लड़की बबीता पांडे गायब हो गईं। पिछले 12 दिन से उसकी तलाश जारी है। 23 वर्षीय बबीता पांडे मूल रूप से नैनीताल के रामनगर क्षेत्र के चिल्किया गांव की रहने वाली हैं। एमबीए छात्रा बबीता पांडे 29 मई की रात से रहस्यमय हालात में लापता हो गईं। उसकी तलाश के लिए SDRF, NDRF, ITBP और पुलिस की टीमों सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। बताया जा रहा है कि बबीता अपने दो दोस्तों के साथ ट्रेकिंग पर गई थी। वो गोई बेस कैम्प में रुके थे। बबीता के दोस्तों ने पुलिस को बताया कि वह आधी रात को टेंट से बाहर गई थी और उसके बाद वापस नहीं लौटी। 12 हजार फीट पर गुम हुई बबीता पांडे का 12 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। 100 जवान, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और डॉग स्कॉड दिन रात बबीता की तलाश में जुटे हैं। पुलिस के अनुसार, बबीता अपने दो दोस्तों के साथ 28 मई को रैथल गांव में रुकी थी, जिसकी फुटेज CCTV में कैद हुई थी। एक दिन बाद, उन्होंने रैथल से दयारा बुग्याल के लिए ट्रेकिंग शुरू की और गोई बेस कैम्प में रात बिताई। लेकिन बबीता कैम्प से लापता हो गईं।

तेलंगाना में इंजीनियर ने बनाई 100 करोड़ की संपत्ति, कैश-सोना जब

हैदराबाद। तेलंगाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने सड़क एवं भवन विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ मोहन नाइक जरूपला को गिरफ्तार किया है। सरकारी सेवा में रहते हुए अपनी आय अधिक संपत्ति के आरोपों के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था इस कार्रवाई के तहत एसीबी अधिकारियों ने कार्यालय, आवास और उनके रिश्तेदारों व सहयोगियों से जुड़े 15 अन्य ठिकानों पर एक साथ छापामारी की। जांचकर्ताओं द्वारा की गई इस व्यापक छापामारी के दौरान भारी मात्रा में अचल संपत्ति का पता चला है। एसीबी के अनुसार, अब तक की खोज में निजामाबाद जिले के डिचपल्ली मंडल के मुल्लांगी गांव में 19.38 एकड़ में फैली पांच कृषि भूमि मिली है, जिनकी सरकारी कीमत लगभग 82.9 लाख रुपये आंकी गई है। इसके अलावा, अधिकारियों को हैदराबाद के आलीशान इलाकों में सात फ्लैट भी मिले हैं, जिनमें से तीन कोमपल्लो और चार गाचीबावली में स्थित हैं।

सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाने के बाद पीएम मोदी ने किया पोस्ट

जनसेवा ही सुशासन की कसौटी

नई दिल्ली, एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज को भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने अपने कार्यकाल के 4,399 दिन पूरे किए और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

प्रधानमंत्री मोदी का यह अहम पड़ाव केंद्र सरकार में उनके 12 साल से ज्यादा के कार्यकाल को दर्शाता है। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा, 'जनसेवा ही सुशासन की सबसे बड़ी कसौटी है। विनम्रता, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा के साथ निरंतर कार्य करने वाला व्यक्ति ही जनविश्वास अर्जित करता है।'

राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पण और सेवाभाव अमूल्य पूंजी रही है

इससे पहले पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के 12 साल पूरे होने पर भी एक पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने लिखा, 'राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पण और सेवाभाव हमारी अमूल्य पूंजी रही है। बीते 12 वर्षों में 'सबका साथ, सबका विकास' की भावना से प्रेरित निरंतर प्रयासों से ही आज हम एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर हैं।'



दिन पूरे कर जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा

सर्जियो गोर ने दी बधाई

अमेरिकी दूत सर्जियो गोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक संदेश में गोर ने लिखा, 'भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। यह उपलब्धि दशकों की उनकी समर्पित जन-सेवा और नेतृत्व का एक सशक्त प्रमाण है! उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएं!'

नेहरू 1947 से लेकर 1964 तक प्रधानमंत्री रहे

नेहरू 1947 से लेकर 1964 में अपनी मृत्यु तक प्रधानमंत्री रहे। हालांकि, उनके कार्यकाल में 1951-52 में भारत के पहले आम चुनाव से पहले के साल भी शामिल थे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लगभग 16 साल तक सेवा की, लेकिन यह कार्यकाल दो अलग-अलग अवधियों में बंटा हुआ था। 26 मई, 2014 को पद संभालने के बाद से पीएम मोदी ने 2019 और 2024 में लगातार जनादेश हासिल किए हैं और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं।

अत्याधुनिक मिसाइल का परीक्षण खाली कराए जा रहे हैं 11 गांव

बालेश्वर। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ आज चांदीपुर के आई टी आर परिसर में स्थित लॉन्चिंग कॉम्प्लेक्स 3 से किसी अत्याधुनिक मिसाइल का परीक्षण करेगा। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।

मिसाइल के परीक्षण की उल्टी गिनती यानी कि काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। परीक्षण स्थल के नजदीक 1 से 3.5 किलोमीटर इलाके में आने वाले करीब 11 गांव को पूरी तरह से खाली कराया जाएगा। आज सुबह 10 बजे से जिला प्रशासन की ओर से उक्त गांव के रहने वाले लोगों को अस्थाई शिविरों में लाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। जब तक मिसाइल का परीक्षण पूरा नहीं हो जाता इन गांव के लोगों को अस्थाई शिविरों में रखा जाएगा, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा तथा खाने पीने का व्यवस्था भी किया गया है। परीक्षण स्थल के नजदीक के गांव है बर्धनपुर, जयदेव कप्पा, शाहजहां नगर इन तीन गांव के 4798 लोगों को बर्धनपुर के हाई स्कूल साइक्लोन सेंटर में रखा जाएगा।

दर्दनाक हदसा: सुंदरनगर आईटीआई के दो प्रशिक्षुओं की मौत, एक घायल

नेरचोक (मंडी)। नागचला क्षेत्र में फोरलेन पर हुए एक भीषण सड़क हादसे में सुंदरनगर आईटीआई के दो प्रशिक्षुओं की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक घायल हो गया। एक मोटरसाइकिल की टुक से टक्कर हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जिला किन्नौर निवासी इमान नेगी और मनोज कुमार परवाणू से जोगिंदरनगर की ओर सामान पहुंचाकर लौट रहे थे। नागचला स्थित फुटब्रिज के समीप वे सड़क पर कर दूसरी ओर जा रहे थे। इसी दौरान, जब मनोज कुमार फोरलेन पर कर रहा था, तभी नागचला की ओर से आ रहे एक ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़े एक अन्य वाहन से जा भिड़ी।

सपना चौधरी से पति ने की मारपीट, बच्चों संग छोड़ा घर, सुबूत लेकर पहुंची कोर्ट

चंडीगढ़। बिग बॉस फेम और मशहूर हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की शादीशुला जिंदगी में भूचाल आ गया है। एक्ट्रेस ने अपने पति पर मारपीट का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं उन्होंने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। वो अपने बच्चों के साथ घर छोड़ने के बाद शरीर पर जखम और गंभीर चोटें लिए अदालत पहुंची। इस मामले को देखते हुईं द्वारा महिला कोर्ट ने सख्त रुख लिया है। कोर्ट ने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के तहत शुरू हुई कार्यवाही में अंतरिम सुरक्षा दी है। कोर्ट ने उनके पति को सुनवाई की अगली तारीख तक उनसे संपर्क करने या उनके पास जाने से रोक दिया है यानी सीधे तौर पर प्रतिबंध लगाया है कि वो सपना चौधरी के आस-पास भी न फटकें। सपना चौधरी ने पति पर लगाए गंभीर आरोप



यह मामला तब सामने आया जब सपना महिला कोर्ट पहुंचीं और आरोप लगाया कि उनके पति ने कई बार उनके साथ मारपीट की और सार्वजनिक रूप से हंगामा किया। उन्होंने पहले कोर्ट को बताया था कि वह अपना घर छोड़कर चली गईं हैं और उनके खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई है।

मेट्रो एंकर

मध्यप्रदेश में हर साल 6 हजार कॉर्निया की जरूरत, मिलते हैं सिर्फ डेढ़ हजार

दो लाख मरीजों को आंखों की रोशनी का इंतजार

भोपाल, दोपहर मेट्रो

मध्य प्रदेश में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस (कॉर्निया की खराबी से होने वाली दृष्टिहीनता) से जूझ रहे हजारों मरीजों के लिए रोशनी का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। स्थिति यह है कि प्रदेश में हर वर्ष करीब 6,000 कॉर्निया की आवश्यकता होती है, लेकिन जागरूकता और संसाधनों की कमी के कारण केवल 1,500 कॉर्निया ही उपलब्ध हो पाते हैं। परिणामस्वरूप करीब 75 प्रतिशत मरीजों को लंबे समय तक प्रतीक्षा करना पड़ती है। स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रान्सप्लांट ऑर्गेनाइजेशन (सोटो) के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में दो लाख से अधिक मरीज कॉर्निया प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा सूची में हैं। हर वर्ष इस सूची में 1,500 से 1,800 नए मरीज और जुड़ जाते हैं। वर्तमान में कॉर्निया प्रत्यारोपण की सुविधा केवल भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों तक सीमित है। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में सबसे अधिक, करीब 100 कॉर्निया प्रत्यारोपण प्रतिवर्ष किए जाते हैं।



जागरूकता की कमी सबसे बड़ी चुनौती

एम्स भोपाल के नेत्र रोग विभाग की प्रमुख डॉ. भावना शर्मा के अनुसार, नेत्रदान को लेकर समाज में फैली भ्रांतियां आज भी सबसे बड़ी बाधा हैं। उन्होंने बताया कि एक मृत व्यक्ति के नेत्रदान से दो दृष्टिहीन मरीजों को रोशनी मिल सकती है, क्योंकि दोनों आंखों से प्राप्त कॉर्निया अलग-अलग दो मरीजों को प्रत्यारोपित किए जाते हैं।

डॉक्टरों की टीम आने तक कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं

शव के आसपास चल रहे पंखे बंद कर दें। आंखों पर साफ और गीली रुई या कपड़ा रखें। मृतक के सिर के नीचे तकिया रखकर सिर को थोड़ा ऊंचा रखें।

हर जिले में सुविधा विकसित करने की जरूरत

सोटो के पूर्व संचालक डॉ. संजय दीक्षित का कहना है कि वर्तमान में प्रदेश की कुल जरूरत का केवल 20 से 25 प्रतिशत कॉर्निया ही दान के रूप में मिल पा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि कॉर्निया डोनेशन और ट्रान्सप्लांट की सुविधाएं अभी केवल बड़े शहरों तक सीमित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों तक यह व्यवस्था पहुंचाना समय की आवश्यकता है।

नेत्रदान में समय का विशेष महत्व

विशेषज्ञों के अनुसार मृत्यु के छह घंटे के भीतर कॉर्निया सुरक्षित निकालना आवश्यक होता है। इसलिए किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद परिजन यदि नेत्रदान के लिए सहमत देते हैं तो तुरंत निकटतम आई बैंक को सूचना देनी चाहिए।